गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 227
दि. 18.12.2025,
गुरुवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

तीन दशक बाद टूटा सत्ता का घमंड, फ्लैट घोटाले ने छीनी माणिकराव कोकाटे की कुर्सी, अजित पवार के सामने सियासी अग्निपरीक्षा

(जीएनएस)। मुंबई। महाराष्ट्र की राजनीति में बुधवार का दिन एक बड़े सियासी झटके के रूप में दर्ज हो गया। फर्जी कागजात के जरिए फ्लैट हासिल करने के 30 साल पुराने मामले में दोषी ठहराए गए अजित पवार गुट के मंत्री माणिकराव कोकाटे को आखिरकार अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। सत्र न्यायालय द्वारा दो साल की सजा बरकरार रखे जाने के बाद कोकाटे का मंत्री पद पर बने रहना असंभव हो गया था। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पत्र के आधार पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने विभागीय बदलाव को मंजूरी दे दी, जिसके बाद माणिकराव कोकाटे के पास रहे सभी विभाग उपमुख्यमंत्री अजित पवार को सौंप दिए गए। इसके साथ ही कोकाटे की विधायकी पर भी संकट के बादल गहराते नजर आ रहे हैं।

बुधवार को राज्य के राजनीतिक गलियारों में नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला। मंगलवार को सत्र न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए माणिकराव कोकाटे को दोषी ठहराया और दो साल की कैद व जुर्माने की सजा कायम रखी। अदालत ने उनकी गिरफ्तारी का आदेश भी जारी किया। बुधवार को कोकाटे उच्च न्यायालय पहुंचे और सजा रद्द करने या कम से कम निलंबित करने की गुहार लगाई, लेकिन कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। इसी के साथ यह लगभग तय हो गया कि उन्हें मंत्री पद ही नहीं, बल्कि विधायक पद से भी इस्तीफा देना पड़ सकता है।

इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बीच अहम बैठक हुई, जिसमें कोकाटे के विभागों को लेकर चर्चा की गई। निर्णय लिया गया कि उनके सभी खाते फिलहाल अजित पवार को सौंपे जाएंगे। कुछ ही देर बाद माणिकराव कोकाटे का इस्तीफा सामने आ गया। हालांकि हाई कोर्ट में पेशी के दौरान उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए चार दिन का समय मांगा और उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इसका राजनीतिक असर शून्य रहा। अब हाई कोर्ट शुक्रवार को उनकी याचिका पर सुनवाई करेगा, हालांकि सजा बरकरार रहने की स्थिति में उनका इस्तीफा औपचारिक रूप से स्वीकार किया जाना तय माना जा रहा है।

जिस मामले ने आज एक मंत्री की सत्ता छीन ली, उसकी जड़ें तीन दशक पुरानी हैं। यह पूरा प्रकरण नासिक के कनाडा कॉर्नर इलाके में स्थित निर्माण व्यू अपार्टमेंट से जुड़ा है। आरोप है कि माणिकराव कोकाटे ने अपने पद और राजनीतिक प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए 'मुख्यमंत्री कोटे' से निम्न आय वर्ग के लिए आरक्षित फ्लैट हासिल किया। यह फ्लैट गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए था, लेकिन नियम-कानूनों को ताक पर रखकर उसे हथिया लिया गया। इस घोटाले में कोकाटे अकेले नहीं थे। उनके भाई विजय कोकाटे के साथ-साथ पोपट सोनावाने और प्रशांत गोवर्धन पर भी मिलीभगत का आरोप लगा। चारों ने मिलकर फ्लैटों का ऐसा आवंटन करवाया, जो नियमों के पूरी तरह खिलाफ था।

इस फर्जीवाड़े का खुलासा उस समय हुआ, जब तत्कालीन राज्य मंत्री तुकाराम दिघोले को इसकी भनक लगी। उन्होंने सरकार में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। जिला प्रशासन ने जांच की तो आरोप सही पाए गए और मामला अदालत पहुंच गया। इसके बाद लंबी कानूनी लड़ाई चली। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कोर्ट ने माणिकराव कोकाटे और उनके भाई को दोषी ठहराते हुए दो साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। कोकाटे को उम्मीद थी कि ऊपरी अदालत से राहत मिल जाएगी, लेकिन मंगलवार को जिला न्यायालय ने उनकी अपील खारिज कर दी और निचली अदालत के फैसले पर मुहर लगा दी। यही वह फैसला था, जिसने उनके राजनीतिक करियर पर पूर्णविराम लगाने की पटकथा लिख दी।

इस पूरे घटनाक्रम में याचिकाकर्ता अंजलि दिघोल राठोड़ की भूमिका बेहद अहम रही। वर्षों तक उन्होंने इस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ी और प्रभावशाली राजनीतिक रसूख के आगे झुकने से इनकार किया। जब हाई कोर्ट में सजा बरकरार रही और कोकाटे के वकील सरेंडर के लिए समय मांग रहे थे, तब अंजलि दिघोल के वकीलों ने कोर्ट में कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने साफ दलील दी कि दोषी चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, उसे कानून से छूट नहीं मिलनी चाहिए। कोर्ट ने उनकी दलीलों को स्वीकार किया और तत्काल गिरफ्तारी वारंट की मांग को सही ठहराया। यही वह मोड़ था, जिसने एक मंत्री को झुकने पर मजबूर कर दिया।

माणिकराव कोकाटे का इस्तीफा अजित पवार गुट के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं माना जा रहा है। कुछ समय पहले ही सरपंच हत्याकांड में नाम आने और विवाद बढ़ने के बाद वरिष्ठ नेता धनंजय मुंडे को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था, जिससे पार्टी की छवि को गहरा झटका लगा था। अब कोकाटे का मामला सामने आने से विपक्ष को बैठे-बिठाए एक और बड़ा मुद्दा मिल गया है।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अजित पवार पर नैतिक दबाव लगातार बढ़ रहा है। एक तरफ नगर निगम चुनाव सिर पर हैं, दूसरी तरफ उनके मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगते जा रहे हैं। जनता के बीच यह संदेश जा रहा है कि सत्ता में बैठे लोग खुद को कानून से ऊपर समझते हैं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या अजित पवार अपने गुट को बचाने के लिए और कड़े फैसले लेंगे या फिर यह मामला उनकी राजनीतिक साख पर और गहरी चोट करेगा। आने वाले दिनों में यह प्रकरण महाराष्ट्र की राजनीति में लंबे समय तक गूंजता नजर आ सकता है।

ऑस्कर की दहलीज़ पर भारतीय फिल्म 'होमबाउंड', दुनिया की टॉप 15 फिल्मों में बनाई जगह

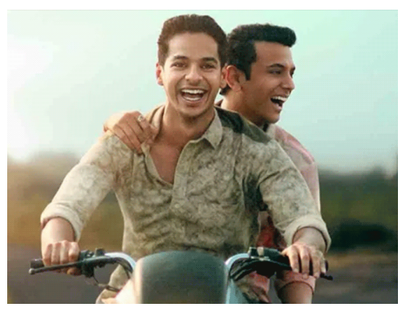

(जीएनएस)। मुंबई। भारतीय सिनेमा के लिए एक बड़ी उपलब्धि सामने आई है, जहां फिल्म निर्देशक नीरज घेवान की बहुप्रशंसित फिल्म 'होमबाउंड' ने 98वें एकेडमी अवॉर्ड्स यानी ऑस्कर की 'बेस्ट इंटरनेशनल फीचर' कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट होकर इतिहास की ओर कदम बढ़ा दिया है। इस उपलब्धि के साथ 'होमबाउंड' दुनिया भर की उन चुनिंदा 15 फिल्मों में शामिल हो गई है, जो अब ऑस्कर की अंतिम दौड़ में बनी हुई हैं। यह न केवल फिल्म से जुड़े कलाकारों और निर्माताओं के लिए गर्व का क्षण है, बल्कि भारतीय सिनेमा की वैश्विक पहचान को और मजबूत करने वाला पल भी माना जा रहा है।

इस फिल्म की खास बात यह है कि हॉलीवुड के दिग्गज निर्देशक मार्टिन स्कोर्सेसी इससे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के तौर पर जुड़े हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी विश्वसनीयता और प्रभाव और भी बढ़ गया है। फिल्म का निर्माण करण जौहर और आदर पूनावाला ने किया है, जिन्होंने इस संवेदनशील और सामाजिक रूप से प्रासंगिक कहानी को वैश्विक मंच तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। ऑस्कर की इस प्रतिष्ठित सूची में 'होमबाउंड' का मुकाबला अर्जेंटीना की 'बेलेन', ब्राजील की 'द सीक्रेट एजेंट', जर्मनी की 'साउंड ऑफ फॉलिंग' समेत 14 अन्य चर्चित अंतरराष्ट्रीय फिल्मों से है, जो अपने-अपने देशों की सर्वश्रेष्ठ सिनेमा का प्रतिनिधित्व कर रही हैं।

'होमबाउंड' को भारतीय सिनेमा की कलात्मकता और सामाजिक यथार्थ का सशक्त उदाहरण माना जा रहा है। यह फिल्म न केवल तकनीकी और अभिनय के स्तर पर प्रभावशाली है, बल्कि समाज में गहराई से जड़ें जमाए जातिगत और धार्मिक भेदभाव जैसे संवेदनशील मुद्दों को भी बेहद मानवीय और सशक्त तरीके से उठाती है। यही वजह है कि यह फिल्म वैश्विक दर्शकों और समीक्षकों का ध्यान खींचने में सफल रही है और ऑस्कर जैसी प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में अपनी जगह बना पाई है। एकेडमी ने इस वर्ष कुल 11 अन्य कैटेगरी में भी शॉर्टलिस्ट फिल्मों की घोषणा की है। 98वें ऑस्कर अवॉर्ड्स के लिए नॉमिनेशन की आधिकारिक घोषणा 22 जनवरी 2026 को की जाएगी, जबकि पुरस्कार समारोह 15 मार्च 2026 को हॉलीवुड के प्रतिष्ठित डॉल्बी थिएटर में आयोजित होगा। हर कैटेगरी में पांच नॉमिनी चुने जाएंगे, जबकि बेस्ट पिक्चर कैटेगरी में दस फिल्मों को नामांकन मिलेगा। इस समारोह का सीधा प्रसारण दुनिया के 200 से अधिक देशों में किया जाएगा, जिससे 'होमबाउंड' को वैश्विक स्तर पर और भी व्यापक दर्शक मिलेंगे। फिल्म की कहानी दो ग्रामीण दोस्तों के इर्द-गिर्द घूमती है, जिनमें से एक मुस्लिम है और दूसरा दलित। दोनों का सपना है कि वे पुलिस की नौकरी हासिल कर समाज में सम्मान और पहचान पा सकें। यह सपना उन्हें एक साझा संघर्ष और गहरी दोस्ती के सूत्र में बांधता है, लेकिन सामाजिक भेदभाव, पहचान की राजनीति और व्यवस्था की सख्त सच्चाइयां उनके रास्ते में लगातार चुनौतियां बनकर खड़ी होती हैं। फिल्म इन दोनों किरदारों की भावनात्मक यात्रा को बेहद संवेदनशीलता और यथार्थ के साथ प्रस्तुत करती है। 'होमबाउंड' प्रसिद्ध पत्रकार बशारत पीर के चर्चित लेख 'टेकिंग अमृत होम' से प्रेरित है, जिसमें ग्रामीण भारत की सामाजिक जटिलताओं और आम लोगों के सपनों को गहराई से उकेरा गया है। फिल्म में ईशान खट्टर, जान्हवी कपूर और विशाल जेठवा ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं, जिनके अभिनय की काफी सराहना हो रही है। कुल मिलाकर 'होमबाउंड' न केवल एक फिल्म है, बल्कि भारतीय समाज की उन परतों को उजागर करने वाली कहानी है, जो अब ऑस्कर के मंच से दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचने के बेहद करीब पहुंच चुकी है।

लोकतांत्रिक आवाज़ों पर दमन का आरोप राज्यसभा में गूंजा लद्दाख आंदोलन का मुद्दा

(जीएनएस)। नई दिल्ली। राज्यसभा में बुधवार को उस समय तीखी बहस और भावनात्मक माहौल देखने को मिला, जब आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय सिंह ने लद्दाख के जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी और लद्दाख आंदोलनकारियों की रिहाई का मुद्दा शून्यकाल में उठाया। संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर लोकतंत्र की बुनियादी आत्मा को कुचलने और असहमति की आवाज़ों का दमन करने का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि शांतिपूर्ण आंदोलनकारियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जैसे कठोर प्रावधान लगाना देश को अघोषित आपातकाल की ओर धकेलने जैसा है, जहां सवाल पूछना और अधिकारों की मांग करना अपराध बना दिया गया है।

संजय सिंह ने सदन में कहा कि सोनम वांगचुक कोई अपराधी नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित जलवायु कार्यकर्ता, शिक्षाविद और नवाचार के प्रतीक हैं, जिन्होंने लद्दाख जैसे दुर्गम हिमालयी क्षेत्र में शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए ऐतिहासिक योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि वांगचुक ने हमेशा संविधान के दायरे में रहकर, अहिंसक और लोकतांत्रिक तरीकों से अपनी बात रखी, इसके बावजूद उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का इस्तेमाल करना यह दर्शाता है कि सरकार अब आलोचना और सवालों से डरने लगी है।

सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का दुरुपयोग कर रही है और इसका उद्देश्य अब देश की सुरक्षा नहीं, बल्कि विरोध की आवाज़ों को दबाना बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस कानून को देश की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए बनाया गया था, उसी कानून का इस्तेमाल आज शांतिपूर्ण आंदोलनकारियों, बुद्धिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को डराने के लिए किया जा रहा है। यह प्रवृत्ति लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है और आने वाले समय में इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

उन्होंने लद्दाख में हुए हालिया घटनाक्रम का जिक्र करते हुए बताया कि 24 सितंबर 2025 को राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की मांग को लेकर हुए प्रदर्शनों के दौरान चार निर्दोष नागरिकों की जान चली गई, 70 से अधिक लोग घायल हुए और 70 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से कई लोगों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया गया और आज भी 10 से अधिक लोग जेल में बंद हैं। संजय सिंह ने कहा कि यह आंकड़े अपने आप में यह साबित करते हैं कि सरकार संवाद की बजाय दमन का रास्ता अपना रही है।

सदन में बोलते हुए संजय सिंह ने लद्दाख के राष्ट्रभक्ति के इतिहास को भी याद दिलाया। उन्होंने कहा कि लद्दाख वही भूमि है जिसने 1948, 1962, 1971 और 1999 के कारगिल युद्ध के साथ-साथ 2020 के सीमा तनाव के दौरान भी देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होकर अद्वितीय राष्ट्रभक्ति का परिचय दिया। ऐसे क्षेत्र के नागरिकों के साथ इस तरह का कठोर और दमनात्मक रवैया अपनाना न सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि देश की एकता और विश्वास को भी कमजोर करता है।

संजय सिंह ने सोनम वांगचुक की पत्नी द्वारा जताई गई चिंताओं का हवाला देते हुए कहा कि जेल में उनकी सुरक्षा को लेकर आशंकाएं, लगातार निगरानी और भय का माहौल बेहद गंभीर विषय है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का खुला उल्लंघन है, जो नागरिकों को समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर संविधान में दिए गए अधिकार ही सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो लोकतंत्र केवल कागज़ों तक सिमट कर रह जाएगा।

अंत में संजय सिंह ने सदन के माध्यम से केंद्र सरकार से मांग की कि सोनम वांगचुक को तत्काल रिहा किया जाए, उनके खिलाफ लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को तुरंत वापस लिया जाए और लद्दाख आंदोलन से जुड़े सभी शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को बिना किसी शर्त के रिहा किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को दमन और टकराव की राजनीति छोड़कर लद्दाख के प्रतिनिधियों के साथ राज्य के दर्जे और छठी अनुसूची को लेकर तुरंत, गंभीर और सार्थक संवाद शुरू करना चाहिए, ताकि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा हो सके और देश में भरोसे का माहौल बना रहे।

सुरक्षा संकट के बीच भारत का कड़ा कदम, ढाका में भारतीय वीजा सेंटर अचानक बंद

(जीएनएस)। ढाका। बांग्लादेश में बिगड़ते सुरक्षा हालात के बीच भारत ने एक अहम और सख्त कदम उठाते हुए ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र को बंद कर दिया है। राजधानी ढाका के जमुना फ्यूचर पार्क में स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र, जो बांग्लादेश में भारत की सभी वीजा सेवाओं का मुख्य और एकीकृत केंद्र माना जाता है, ने बुधवार को दोपहर बाद अपना कामकाज पूरी तरह रोक दिया। इस फैसले को भारत की ओर से सुरक्षा को लेकर गंभीर चेतावनी और कूटनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है।

भारतीय वीजा आवेदन केंद्र ने जारी अपने आधिकारिक बयान में कहा कि मौजूदा सुरक्षा स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। बयान में स्पष्ट किया गया कि जमुना फ्यूचर पार्क स्थित केंद्र को बुधवार को अपराह्न दो बजे बंद कर दिया गया। इसके साथ ही यह भी बताया गया कि जिन आवेदकों के लिए बुधवार को वीजा आवेदन जमा करने के अपॉइंटमेंट तय थे, उनके सभी अपॉइंटमेंट बाद की तारीख के लिए पुनर्निर्धारित किए जाएंगे। अचानक लिए गए इस फैसले से वीजा सेवाओं पर निर्भर हजारों लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है।

इस घटनाक्रम से पहले दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हमीदुल्लाह को तलब किया था। मंत्रालय ने ढाका में भारतीय मिशन के आसपास कुछ चरमपंथी तत्वों द्वारा सुरक्षा संकट पैदा करने की साजिश की घोषणाओं को लेकर गहरी चिंता जताई। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत को बांग्लादेश में अपने राजनयिक मिशनों और कार्यालयों की सुरक्षा को लेकर गंभीर आशंकाएं हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। विदेश मंत्रालय के बयान में यह भी कहा गया कि भारत अंतरिम बांग्लादेशी सरकार से यह अपेक्षा करता है कि वह अपने कूटनीतिक दायित्वों के तहत भारतीय मिशन और उससे जुड़े कार्यालयों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। उच्चायुक्त को यह साफ तौर पर अवगत कराया गया कि बांग्लादेश में मौजूदा सुरक्षा माहौल भारत के लिए चिंता का विषय बन गया है और इस पर तत्काल प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि ढाका में वीजा सेंटर का बंद होना केवल एक प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि इसके पीछे एक स्पष्ट राजनीतिक और कूटनीतिक संदेश छिपा है। भारत यह संकेत देना चाहता है कि अपने नागरिकों, राजनयिकों और संस्थानों की सुरक्षा के मामले में वह किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाएगा। यदि हालात में सुधार नहीं होता है, तो आने वाले दिनों में भारत-बांग्लादेश के संबंधों पर इसका असर और गहराता नजर आ सकता है।

भारत–इथियोपिया संबंधों को नई ऊंचाई, रणनीतिक साझेदारी में बदले रिश्ते, आठ अहम समझौतों से मजबूत हुआ भरोसा

(जीएनएस)। अदीस अबाबा। भारत और अफ्रीकी देश इथियोपिया के बीच दशकों पुराने मित्रवत और भरोसेमंद संबंधों ने बुधवार को एक नया और ऐतिहासिक मुकाम हासिल कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबिय अहमद अली के बीच हुई व्यापक और सार्थक वार्ता के बाद दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय रिश्तों को औपचारिक रूप से 'रणनीतिक साझेदारी' के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया। इस महत्वपूर्ण अवसर पर दोनों पक्षों के बीच कुल आठ अहम समझौतों और करारों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनका उद्देश्य सहयोग को केवल कूटनीतिक दायरे तक सीमित न रखते हुए विकास, तकनीक, शिक्षा, स्वास्थ्य और जनकल्याण तक विस्तार देना है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कहा कि इथियोपिया के साथ हुए ये समझौते विकास और जन-केंद्रित साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम हैं। उन्होंने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर अपने संदेश में लिखा कि ये करार भारत और इथियोपिया के बीच लंबे समय से चली आ रही भरोसेमंद दोस्ती को आगे बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होंगे। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों का साझा फोकस शासन, शांति स्थापना, डिजिटल क्षमता निर्माण, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में लोगों को सशक्त बनाने पर है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ज्ञान, कौशल और नवाचार पर दिया गया महत्व इस विश्वास को दर्शाता है कि युवा ही भविष्य को आकार देने की सबसे बड़ी ताकत हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी रेखांकित किया कि स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग, विशेषकर मातृ और नवजात स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की पहल, मानव गरिमा और समाज के सबसे कमजोर वर्गों की देखभाल के प्रति दोनों देशों की गहरी प्रतिबद्धता को दिखाती है। उनके अनुसार, इन समझौतों के जरिए यह स्पष्ट हो गया है कि भारत–इथियोपिया साझेदारी केवल रणनीतिक नहीं, बल्कि विकासोन्मुख और जन-केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित है।

इस द्विपक्षीय वार्ता के दौरान जिन प्रमुख समझौतों पर सहमति बनी, उनमें दोनों देशों के रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी में अपग्रेड करना सबसे अहम माना जा रहा है। इसके अलावा सीमा शुल्क मामलों में सहयोग और आपसी प्रशासनिक सहायता, इथियोपिया के विदेश मंत्रालय में एक आधुनिक डेटा सेंटर की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों के लिए प्रशिक्षण सहयोग की कार्यान्वयन व्यवस्था, जी-20 के कॉमन फ्रेमवर्क के तहत ऋण पुनर्गठन पर सहमति, इथियोपियाई छात्रों के लिए आईसीसीआर छात्रवृत्ति की संख्या को दोगुना करना, आईटीईसी पहल के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में विशेष अल्पकालिक पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना और मातृ व नवजात स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने जैसे अहम विषय शामिल हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि इन समझौतों से भारत और इथियोपिया के बीच आर्थिक, तकनीकी और मानवीय सहयोग को नई गति मिलेगी। अफ्रीका में भारत की बढ़ती भूमिका और इथियोपिया के साथ रणनीतिक साझेदारी न केवल द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करेगी, बल्कि वैश्विक मंच पर दक्षिण-दक्षिण सहयोग की एक मजबूत मिसाल भी पेश करेगी। यह साझेदारी ऐसे समय में और भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जब वैश्विक स्तर पर विकास, शांति और सतत प्रगति के लिए भरोसेमंद साझेदारियों की जरूरत बढ़ती जा रही है।

संपादकीय

अमीरी दे गरीब को त्रास

देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली घातक पर्यावरण संकट झेल रही है। विडंबना यह है कि इस संकट के निदान के लिये जो उपाय लागू किए जा रहे हैं, उसका खमियाजा गरीबों को झेलना पड़ रहा है। इस संकट की संवेदनशीलता को महसूस करते हुए सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि अमीरों की जीवन शैली से उपजी मुश्किलों का सामना गरीबों को करना पड़ता है। दरअसल, बिगड़ते प्रदूषण संकट के बाबत दायर याचिकाओं को आज सुनवाई के लिये सूचीबद्ध करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने यह मर्मस्पर्शी टिप्पणी की। कोर्ट ने भरोसा दिलाया कि वह इस बाबत प्रभावी और लागू करने योग्य आदेश पारित करेगा। दरअसल, मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने वरिष्ठ वकील और न्यायमित्र अपराजिता सिंह की दलीलों पर गौर करते हुए ये टिप्पणी की थी। अदालत का कहना था कि दिल्ली एनसीआर में ग्रेप-4 लागू करने के चलते जो पाबंदियां लागू की गई हैं, उनका सबसे ज्यादा नुकसान गरीब लोगों को हो रहा है। इससे निर्माण कार्य बंद होने से हजारों गरीब मजदूरों का चूल्हा नहीं जल सकेगा। मुख्य न्यायाधीश ने इस बाबत कहा कि संपन्न लोगों को अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना चाहिए। साथ ही कहा कि हमें समस्या का पता है और इसलिए हम ऐसे आदेश पारित करेंगे, जिनका पालन किया जा सकेगा। कहा कि कुछ निर्देश ऐसे भी हैं, जिन्हें बलपूर्वक लागू किया जा सकता है। जस्टिस सूर्यकांत का कहना था कि महानगरों में लोगों की अपनी अलग जीवनशैली होती है, जिन्हें वे बदलना नहीं चाहते। यही वजह है कि समस्या अमीरी की वजह से होती है, लेकिन झेलना गरीब को पड़ता है। दरअसल, अदालत की सोच रही है कि हमारा परिवेश-पर्यावरण साफ-सुथरा रहे, इसके लिये हम सबको अपने कुछ सुखों का त्याग करना होगा। यह जानते हुए कि पर्यावरण पर आने वाले संकट व प्रदूषित हवा का अमीर-गरीब पर समान असर पड़ता है।

निस्संदेह, देश की शीर्ष अदालत ने देश व समाज की दुखती रग पर ही हाथ रखा है। महानगरों में अमीर तबके की विलासिता के चलते ही पर्यावरण व अन्य संकटों को बढ़ावा मिलता है। महानगरों में लगातार सड़कों का विस्तारीकरण, नए हाइवे निर्माण व ओवर ब्रिज निर्माण के बावजूद जाम व प्रदूषण का संकट कम नहीं हो रहा है। दरअसल, हमने अपनी सुख-सुविधाओं को प्राथमिकता दी है, लेकिन व्यापक सामाजिक हितों की अनदेखी की है। आमतौर पर एक अकेले व्यक्ति के लिये कारें सड़कों पर दौड़ती रहती हैं। जो न केवल सड़कों में ज्यादा जगह घेरती हैं, बल्कि ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करके प्रदूषण को भी बढ़ावा देती हैं। यही वजह है कि आम आदमी सरकार ने अपने कार्यकाल में ऑड-इवन प्रणाली शुरू करने को प्राथमिकता दी थी ताकि सड़कों पर कारों का सैलाब कम किया जा सके। तब बात उठी थी कि एक दिशा में और एक ऑफिस की तरफ जाने वाले लोग कार शेयर करके चलें। विडंबना यह है कि सत्ताधीशों ने दिल्ली में सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट को सशक्त करने को प्राथमिकता नहीं दी। यदि सार्वजनिक परिवहन सस्ता व सहज उपलब्ध होता तो शायद सड़कों पर कारों का दबाव कम होता। हाल के दिनों में संपन्न व मध्यम वर्ग में एसी व अन्य वातानुकूलन उपायों के उपयोग का प्रचलन तेजी से बढ़ा है। इससे जहां प्रदूषण बढ़ाने वाली बिजली की खपत बढ़ी है, वहीं बाहर का तापमान व कार्बन उत्सर्जन भी बढ़ा है। इसी तरह तमाम अमीरों द्वारा संचालित उद्योगों में उन उपायों का ईमानदारी से पालन नहीं किया गया जो पर्यावरण में प्रदूषण कम करने में सहायक होते हैं। विडंबना यह है कि महानगरों व अन्य शहरों में जहां कुछ इलाकों में पेयजल का संकट बना रहता है, वहीं दूसरे पॉश इलाकों मे लॉन सींचने, कार धोने और स्वीमिंग पूलों के लिये पर्याप्त पानी उपलब्ध रहता है। अकसर कहा जाता है कि कुदरत ने हर व्यक्ति के लिए हवा, पानी व भोजन उपलब्ध कराया है, लेकिन इनके असमान वितरण व अमीरी के दखल के चलते, गरीब के साथ न्याय नहीं हो पाता है। अमीर होना बुरा नहीं है लेकिन उसकी अमीरी की कीमत गरीब को न चुकानी पड़े।

आपराधिक मामलों के निपटान में देरी अन्याय जैसा

> भारत में आपराधिक मामलों के निर्णय में देरी न्याय प्रणाली में अन्तर्निहित है। यह देरी न्याय से वंचित करने के समान ही है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकान्त द्वारा लम्बित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का एजेंडा तय करना प्रशंसनीय पहल है। इसके लिए बहु-आयामी रणनीति की जरूरत है।

एक दिवंगत रेलवे टीटीई को 50 रुपये की रिश्वतखोरी के आरोप से मुक्त होने में 40 साल लग गए, जिसके कारण अपने जीवन-काल में उन्हें सरकारी नौकरी, सम्मान और मानसिक शांति खोने का दंश झेलना पड़ा था। मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन में तैनात लिपिक, जागेश्वर प्रसाद अवधिया को 100 रुपये रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तारी के 39 वर्ष बाद सर्वोच्च न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया। वर्ष 2005 और 2006 के सबसे चौंकाने वाले निठारी सीरियल किलिंग मामलों में नवम्बर, 2025 में सर्वोच्च न्यायालय ने सुरेन्द्र कोली और पंढेर को भी दोषमुक्त कर दिया है। वस्तुतः भारत में आपराधिक मामलों के निर्णय में देरी आपराधिक न्याय प्रणाली में अन्तर्निहित है, जिसके परिणाम स्वरूप गिरफ्तार किए गए सभी लोगों में से 46 प्रतिशत से अधिक को विचाराधीन कैदियों के रूप में विभिन्न अवधियों के लिए जेलों में सजायाफ्ता दोषियों की तरह कष्ट सहने को मजबूर होना पड़ रहा है। इस पृष्ठभूमि में, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकान्त द्वारा लम्बित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का एजेंडा तय करना प्रशंसनीय पहल है।

29 अक्तूबर, 2025 को भी आरोप निर्धारण में अत्यधिक देरी पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गम्भीर चिन्ता व्यक्त की गई थी और इस समस्या के समाधान के लिए समुचित दिशा-निर्देश निर्धारित करने हेतु भारत के महान्यायवादी और सॉलिसिटर जनरल से सहयोग मांगा था। आपराधिक मामलों के निपटान में देरी महज आकस्मिक नहीं, जिसे दिशा-निर्देश बनाकर रोका जा सके, वास्तव में यह उभरती दरपेश परिस्थितियों से निपटने में संस्थागत विफलता का मामला है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के प्रकाशन 'भारत में अपराध-2023' के अनुसार, पिछले वर्ष के लम्बित 2,45,84,673 मामलों में इस वर्ष 8,25,681

और आपराधिक मामलों की बढ़ोतरी हुई, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2023 के अन्त तक देश में कुल 2,54,10,354 आपराधिक मामले निचली अदालतों में लम्बित हो गए। इस वर्ष न्यायालयों द्वारा 40,95,080 आपराधिक मामलों का ही निपटान सम्भव हो सका जबकि इस दौरान 49,20,771 नए मामले निर्णय के लिए अदालतों में प्राप्त हुए। इस प्रकार लम्बित मामलों की संख्या में प्रतिवर्ष औसतन 16 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। लम्बित आपराधिक मुकदमों के पीछे के कारणों को समझने के लिए गहन विश्लेषण और शोध की आवश्यकता है। इस बढ़ते रुझान को रोकने और लम्बित मामलों की संख्या को कम करने के लिए एक बहु-आयामी रणनीति अपनाने की जरूरत है। इस रणनीति में निम्नलिखित आयाम शामिल किए जा सकते हैं :

पहला, इस मिथक को तोड़ने की आवश्यकता है कि एक पुलिस थाना क्षेत्र के मुकदमों की सुनवाई के लिए एक ही ट्रायल कोर्ट हो सकता है। लम्बित मुकदमों की संख्या के आधार पर एक थाना क्षेत्र में एक से अधिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए जाने चाहिए। कहने की आवश्यकता नहीं कि प्रत्येक ट्रायल कोर्ट में ढांचागत सुविधाओं के साथ-साथ कम से कम तीन स्टेनोग्राफर और दो लोक अभियोजकों की तैनाती का प्रावधान हो। जब तक नियमित पीठासीन अधिकारियों, अभियोजकों, सचिवीय कर्मचारियों की भर्ती नहीं हो जाती और अदालत कक्ष नहीं बन जाते, तब तक जिला जज को अदालतों के लिए भवन किराए पर लेने के लिए और अस्थायी अदालतों के संचालन हेतु सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त करने का अधिकार दिया जा सकता है। दूसरा, कई राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में एक ही न्यायाधीश आपराधिक और सिविल दोनों क्षेत्राधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं। यदि क्षेत्राधिकार विभाजित कर दिया जाए और विभिन्न प्रकृति के मामलों से निपटने के लिए अलग-अलग मजिस्ट्रेट/सिविल जज नियुक्त कर दिए जाएं तो इससे मुकदमों का शीघ्र निपटान सम्भव होगा। कुछ राज्यों में यह प्रथा लागू भी है।

तीसरा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) की धारा 359 में संशोधन करके 'समझौता योग्य मामलों' की सूची में विस्तार किया जा सकता है और 3 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय सभी अपराधों को समझौता योग्य अपराध घोषित करके उनका 'शीघ्र निपटान' सुनिश्चित किया जा सकता है। भारत में अपराध, 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2023 में केवल 3,03,802 छोटे आपराधिक मामलों में ही पक्षकारों द्वारा समझौता किया गया जो कुल पंजीकृत मामलों का लगभग एक प्रतिशत है।

चौथा, बीएनएसएस में प्रावधान है कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध और सामाजिक-आर्थिक अपराधों संबंधी मामलों को छोड़कर बाकी सभी अपराधों में जहां 7 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है, पक्षकार आपसी सहमति से मुकदमों का निपटारा कर सकते हैं जिसे 'प्ली-बार्गेनिंग' की संज्ञा दी गई है। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 में केवल 42,318 मामलों का ही प्ली-बार्गेनिंग के माध्यम से निपटान किया जा सका था। इस प्रावधान में कुछ कमियां हैं। प्ली-बार्गेनिंग के सम्बन्धित प्रावधानों में संशोधन करके प्ली-बार्गेनिंग करने वाले अपराधी के सिर से अपराधी का टैग हटाया जा सकता है। अमेरिका में पहले से ही ही ऐसा प्रावधान है। इसके अलावा, पक्षकारों को यह भी छूट हो कि आपराधिक कार्यवाही के प्रत्येक चरण में वे प्ली-बार्गेनिंग की प्रक्रिया अपनपाकर अपने मुकदमों का फैसला करवा सकें।

पांचवां, आपराधिक मामलों की त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने को बीएनएसएस में कई प्रावधान शामिल किए गए हैं, जिनमें समयबद्ध आरोप तय करना, अदालत में गवाही के लिए विशेषज्ञों को बुलाने की गुंजाइश सीमित करना, पोर्टल पर समयबद्ध तरीके से फैसले अपलोड करना, मुकदमों से पहले केस सम्पत्तियों का निपटान, रिमांड और साक्ष्य दर्ज करने को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा का प्रयोग और 3 वर्ष तक की कैद की सज़ा वाले अपराधों के लिए 'सम्मरी ट्रायल' द्वारा सुनवाई का दायरा बढ़ाना शामिल है। इन कानूनी प्रावधानों का सही तरीके से प्रयोग सुनिश्चित करने और उनकी निगरानी के लिए एक तंत्र स्थापित करने की जरूरत है।

छठा, पर्याप्त संख्या में अभियोजकों, आशुलिपिकों और लिपिकों के न होने और अदालतों के काम के बोझ में दबे होने के कारण अनेक बार अदालतों में बुलाए गए गवाहों से दिन के समाप्त हो जाने तक पूछताछ नहीं हो पाती है। इस स्थिति में सुधार किया जा सकता है। सातवां, रिक्तियों की पूर्ति हेतु न्यायाधीशों, अभियोजकों और अदालती कर्मचारियों की वार्षिक आधार पर नियमित भर्तियां की जानी चाहिए और सम्बन्धित हाईकोर्ट इस सम्बन्ध में हुई प्रगति की निगरानी कर सकते हैं।

आठवां, सुप्रीम कोर्ट में लगभग 18 हजार से अधिक और हाईकोर्टों में 63 हजार से अधिक आपराधिक मामले लम्बित हैं। इन अदालतों में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने और मौजूदा रिक्तियों को भरने के अलावा इन लम्बित मामलों को कम करने का अन्य कोई उपाय प्रतीत नहीं होता है।

ब्रिटिश राजनेता विलियम इवार्ट ग्लैडस्टोन ने कहा था 'न्याय में देरी न्याय से इंकार करने के समान है।' एक कल्याणकारी राज्य अपने लोगों को समय पर न्याय से वंचित नहीं कर सकता, वरना विकास प्रक्रिया अराजकता का शिकार हो जाएगी। सरकारों को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को गम्भीरता से लेकर न्याय देने में हो रही देरी को रोकने के अभियान में स्वेच्छा से भागीदार बनना चाहिए।

प्रेरणा

अक्षरों से दोस्ती: एक अधूरी उम्र में पूरा हुआ सपना

कार्तियानी अम्मा का जीवन उस खामोश संघर्ष की कहानी है, जिसे समाज अक्सर देख नहीं पाता। बचपन से ही उनका संसार घर की चारदीवारी, रिश्तों की जिम्मेदारियों और रोज़मर्रा के कामों में सिमटा रहा। पढ़ाई उनके जीवन का हिस्सा नहीं बन सकी, क्योंकि उस समय परिवार की ज़रूरतें और परिस्थितियाँ सबसे ऊपर थीं। उन्होंने बिना शिकायत किए अपनी ज़िंदगी परिवार को समर्पित कर दी, लेकिन मन के किसी कोने में पढ़ने-लिखने की चाह हमेशा जीवित रही। जैसे-जैसे उम्र बढ़ी, यह चाह और गहरी होती चली गई। जब वे दूसरों को पढ़ते-लिखते देखतीं, तो भीतर कहीं एक टीस उठती—काश, वे भी शब्दों को समझ पातीं, काग़ज़ पर अपने विचार लिख पातीं। वर्षों तक यह भावना मन में दबी रही, लेकिन पूरी तरह कभी बुझी नहीं। इसी दौरान उनकी बेटी अमिनी अम्मा ने मां की इस अधूरी इच्छा को पहचान लिया। एक साधारण-सा वाक्य—"अब भी पढ़ सकती हो"—ने कार्तियानी अम्मा के भीतर छिपे साहस को जगा दिया। यह आसान फैसला नहीं था। जिस उम्र में लोग आराम और विश्राम की ओर

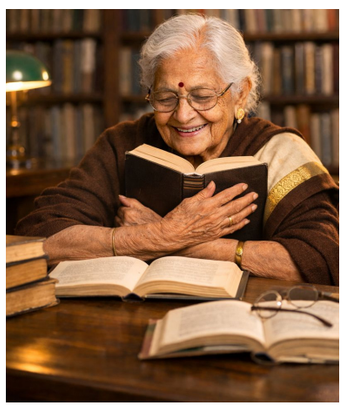

बढ़ते हैं, उस उम्र में पढ़ाई शुरू करना खुद को समाज के सवालों और अपनी सीमाओं के सामने खड़ा करने जैसा था। फिर भी उन्होंने पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ने का रास्ता चुना। उन्होंने केरल राज्य साक्षरता मिशन अथॉरिटी द्वारा आयोजित 'अक्षरलक्ष्यम' साक्षरता परीक्षा में शामिल होने का निर्णय लिया। यह परीक्षा उन लोगों के लिए होती है, जिन्हें बचपन में स्कूल जाने का मौका नहीं मिला और जो जीवन के किसी भी मोड़ पर सीखना चाहते हैं। तैयारी के दिन उनके लिए एक नई दुनिया से परिचय जैसे थे। अक्षरों को पहचानना, शब्दों को जोड़ना और संख्याओं को समझना—यह सब उनके लिए बिल्कुल नया अनुभव था। उम्र के साथ आई शारीरिक थकान, कमजोर होती याददाश्त और धीमी गति हर कदम पर चुनौती बनकर सामने आई, लेकिन कार्तियानी अम्मा ने इन बाधाओं को कभी अपने लक्ष्य के आड़े नहीं आने दिया। उन्होंने बार-बार अभ्यास किया, गलतियां कीं, सुधारा और आगे बढ़ती रहीं। यह सफर केवल पढ़ाई का नहीं, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के पुनर्जागरण का भी था। जब परीक्षा का परिणाम आया, तो किसी ने नहीं सोचा था कि यह इतनी बड़ी मिसाल बनेगा। 96 वर्ष की उम्र में कार्तियानी अम्मा ने 100 में से 98 अंक प्राप्त कर सबको चौंका दिया। यह उपलब्धि केवल एक परीक्षा पास करने तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह उस सोच की जीत थी जो मानती है कि सीखने की कोई तय उम्र नहीं होती। उनकी सफलता ने यह साबित कर दिया कि अगर मन में सीखने की सच्ची चाह हो, तो उम्र केवल एक संख्या बनकर रह जाती है। उनके इस असाधारण प्रयास ने उन्हें देश और दुनिया में पहचान दिलाई। वर्ष 2019 में उन्हें कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग का गुडविल एंबेसडर नियुक्त किया गया, जिससे वे वैश्विक स्तर पर शिक्षा और साक्षरता की प्रेरक आवाज़ बन गईं। इसके बाद वर्ष 2020 में भारत सरकार ने उन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। यह सम्मान उनके व्यक्तिगत संघर्ष के साथ-साथ उन अनगिनत महिलाओं के सपनों का भी सम्मान था, जिन्हें कभी पढ़ने का मौका नहीं मिला। कार्तियानी अम्मा ने यह साबित कर दिया कि सीखने की शुरुआत किसी भी उम्र में की जा सकती है। वर्ष 2023 में उनका निधन हो गया, लेकिन वे अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गईं, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। आज वे हमारे बीच नहीं हैं, फिर भी उनका जीवन संदेश देता है कि सपने उम्र नहीं देखते, और शिक्षा का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। उनका जुनून, उनका साहस और उनका विश्वास हर उस व्यक्ति को आवाज़ देता है, जो अब भी सीखने की हिम्मत जुटा रहा है।

निजीकरण के वर्चस्व से उपजे संकट से सबक लें

वर्ष 1991 के आर्थिक सुधारों ने सार्वजनिक क्षेत्र के एकाधिकार को तोड़ा और निजी कंपनियों को आमंत्रित किया। शुरू में रफ्तार धीमी रही, लेकिन 2000 के बाद इसमें तेजी आई। समस्या तब पैदा हुई जब सरकारों ने सभी समस्याओं का हल निजीकरण मान लिया। इससे दक्षता वृद्धि और राजस्व में बढ़ोतरी जैसे फायदे तो हुए, लेकिन नुकसान भी कम नहीं हुआ। एकाधिकार-मनमानी जैसी समस्याएं पैदा हुईं, जनता तो परेशान हो ही रही है, सरकार भी इन कंपनियों की ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रही है। ताजा उदाहरण भारत के विमानन क्षेत्र का है।

पिछले दिनों विमानन क्षेत्र में इंडिगो एयरलाइन की मोनोपॉली के कारण देश के विभिन्न एयरपोर्ट्स पर बस और रेलवे स्टेशनों से भी बदतर हालात दिखे। इससे साफ है कि निजी कंपनियों पर आंख बंद करके भरोसा करने से देश कभी भी बड़ी मुश्किल में फंस सकता है। साल 2006 में दिल्ली-मुंबई के बीच उड़ान से शुरू हुई इंडिगो आज भारत के विमानन बाजार में सबसे बड़ी खिलाड़ी है और इसके पास करीब 64 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। उसकी विकास यात्रा जितनी हैरत में डालने वाली है, उतनी ही निराशाजनक और चिंता की बात यह है कि उसके कारण लाखों यात्रियों को भारी परेशानी हुई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि भी प्रभावित हुई। जिससे इंडिगो के एकाधिकार पर सवाल उठे । साल 1991 से पहले आसमान पर सरकारी एयरलाइन का ही राज था। एयर इंडिया विदेशों के लिए उड़ती थी और इंडियन एयरलाइंस घरेलू बाजार पर काबिज थी। उदारीकरण का दौर आया तो निजी एयरलाइंस के लिए रास्ते खुले और नई एयरलाइंस की बाढ़—सी आ गई। सवाल यह है कि अब कुछ चुनिंदा एयरलाइंस ही क्यों रह गईं और इस क्षेत्र पर इंडिगो का ही एकाधिकार कैसे हो गया। भारत के घरेलू विमानन बाजार में इंडिगो का वर्चस्व वैश्विक स्तर पर असामान्य है। अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, ब्राजील, जापान, थाईलैंड या फ्रांस जैसे बाजारों में किसी कंपनी का ऐसा एकछत्र राज दिखाई नहीं देता। भारतीय बाजार दो प्रमुख कंपनियों—इंडिगो और एयर इंडिया के कब्जे में है, जिनके पास संयुक्त रूप से करीब 90 फीसदी हिस्सा है। इंडिगो की नाकामी या यूं कहें मनमानी के कारण पूरे भारत के एयरपोर्ट्स पर अफरा-तफरी का माहौल बना। मामले की जांच भी शुरू हो गई, लेकिन एयरलाइन को वह राहत दे दी गई जो वह चाहती थी। भारत के एविएशन रेगुलेटर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) ने इंडिगो को अपने पायलटों के लिए नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (एफडीटीएल) नियमों में अस्थायी छूट दे दी। विशेषज्ञों का कहना है कि जो कुछ हुआ है, उससे यह संदेश गया है कि कोई एक बड़ी कंपनी नियमों में बदलाव करा सकती है, जिससे पूरे भारत की साख प्रभावित हुई है।

किसी एक कंपनी के एकाधिकार की समस्या विमानन क्षेत्र तक सीमित नहीं है। यह मोनोपॉली हर सेक्टर में खड़ी हो गई है। स्टील, माइनिंग, पावर, दूरसंचार, ट्रांसपोर्ट, पेट्रोलियम– हर जगह धीरे-धीरे कुछ कंपनियों का एकाधिकार कायम हो रहा है। दूसरी ओर निजीकरण के चलते सरकारी कंपनी बीएसएनएल और एमटीएनएल को हाशिए पर धकेल दिया गया। अब दूसरी छोटी कंपनियों को रौंदते हुए एक-दो कंपनियों का ही यहां राज चल रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि निजीकरण के चलते डेटा क्रांति हुई। वर्तमान में भारतीय दूरसंचार बाजार तेजी से बढ़ता हुआ बाजार है, जिसमें 1.2 बिलियन से अधिक ग्राहक हैं। डिजिटल इंडिया के विस्तार, स्मार्टफोन के बढ़ते इस्तेमाल और नई तकनीकों में निवेश के कारण यह बाजार फल-फूल रहा है। इस सुनहरी तस्वीर से इतर देखें तो यहां रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया जैसे गिने-चुने ऑपरेटर ही रह गए हैं। रिलायंस जियो की दूरसंचार बाजार में 40 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी है। जिससे एकाधिकार ने नई समस्या पैदा की। बैंकिंग क्षेत्र भी इसी राह पर है। बड़े निजी बैंकों पर ज्यादा भरोसा किया जा रहा है। सरकारी बैंकों का भी निजीकरण हो रहा है। निजी बैंक संपन्न वर्ग के लिए ही काम करने के इच्छुक होते हैं। इनके न्यूनतम बैलेंस भी बहुत ज्यादा रखे गए हैं, जिससे सामान्य व्यक्ति तो इनमें खाता ही नहीं खुलवा पाता। अच्छी सेवा का दावा करने वाले निजी बैंकों की शिकायतें भी खूब आ रही हैं। हालत यह है कि वित्त वर्ष 2024-25 में निजी क्षेत्र के बैंकों के खिलाफ शिकायतें सरकारी बैंकों से अधिक रहीं।

रेलवे के निजीकरण को लेकर भी अटकलें लगाई जाती हैं। यह अलग बात है कि सरकार ने साफ कर दिया है कि इसका निजीकरण नहीं होगा, लेकिन इसकी कई सेवाओं को निजी क्षेत्र में दे दिया गया है। विमानन क्षेत्र में निजी कंपनी के खेल के बाद रेलवे जैसे राष्ट्रीय महत्व और सुरक्षा से जुड़े उपक्रम को निजीकरण के किसी भी षड्यंत्र से दूर रखा जाना आवश्यक हो गया है। वहीं सड़क परिवहन के निजीकरण के प्रयोग भी घातक साबित हुए हैं। मध्यप्रदेश इसका उदाहरण है। वहां निजी बसों की मनमानी के बाद अब सरकारी रोडवेज बसें पुनः शुरू की जा रही हैं। जिन राज्यों में सरकारी रोडवेज बसें चल रही हैं, वहां निजी बसों की मनमानी पर अंकुश लगा हुआ है। साफ है कि आंख मूंदकर हर क्षेत्र में निजीकरण को बढ़ावा देने और कुछ कंपनियों का दबदबा कायम होने के घातक परिणाम होते हैं। यदि निजीकरण जरूरी है तो निगरानी, नियमन व प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। बिना नियंत्रण के यह 'मोनोपॉली मॉडल' अर्थव्यवस्था को कमजोर करेगा, देश को नुकसान पहुंचाएगा और जनता की मुश्किल बढ़ाएगा।

अभियान

जब जीवन बार-बार ठोकर खाए, तब गुरु की शरण बनता है गुरुवार

जीवन में कई ऐसे दौर आते हैं जब मेहनत के बावजूद सफलता दूर रहती है, रिश्ते बनते-बिगड़ते रहते हैं, निर्णय गलत हो जाते हैं और मन में निरंतर असंतोष बना रहता है। ऐसे समय में ज्योतिष शास्त्र यह संकेत देता है कि व्यक्ति का बृहस्पति ग्रह कमजोर या अशुभ अवस्था में हो सकता है। बृहस्पति केवल एक ग्रह नहीं, बल्कि जीवन में ज्ञान, विवेक, धर्म, भाग्य और सही दिशा का प्रतिनिधि है। जब गुरु दुर्बल होते हैं, तो व्यक्ति सही रास्ता होते हुए भी भटकने लगता है। ऐसे समय में गुरुवार का व्रत एक साधारण धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन को संतुलन में लाने का प्रभावी माध्यम बन जाता है।

गुरुवार को बृहस्पति का दिन माना गया है और यह दिन ब्रह्मा तत्व से भी जुड़ा हुआ है। जिन लोगों की कुंडली में गुरु छठे, सातवें, आठवें या दसवें भाव में स्थित होते हैं, उनके जीवन में संघर्ष, रुकावट और मानसिक अस्थिरता अधिक देखने को मिलती है। कई बार व्यक्ति को स्वयं समझ नहीं आता कि सब कुछ होते हुए भी सुख क्यों नहीं है। धनु और मीन राशि के जातकों के लिए तो गुरु स्वयं स्वामी ग्रह होते हैं, इसलिए इनके लिए गुरुवार का व्रत और भी अधिक प्रभावशाली माना गया है। यह व्रत उनके जीवन में स्थिरता और आत्मविश्वास लौटाने का कार्य करता है।

जब बृहस्पति शत्रु ग्रहों जैसे शुक्र या बुध के साथ बैठ जाएं या राहु के प्रभाव में आ जाएं, तब व्यक्ति का विवेक कमजोर होने लगता है। निर्णय भावनाओं या भ्रम में लिए जाने लगते हैं, जिससे नुकसान होता है। ऐसी स्थिति में गुरुवार का व्रत गुरु तत्व को पुनः जागृत करता है। ज्योतिष मानता है कि भाग्य का द्वार बृहस्पति के हाथ में होता है। गुरु जब मजबूत होते हैं, तो चौथा भाव सुख देता है, पांचवां भाव बुद्धि और संतान का योग बनाता है और नौवां भाव भाग्य को प्रबल करता है। यही कारण है कि गुरु की कृपा से ही जीवन में स्थायित्व आता है।

विवाह में देरी, बार-बार संबंधों का टूटना, वैवाहिक जीवन में तनाव या संतान सुख में बाधा—इन सबके पीछे भी गुरु की कमजोरी मानी जाती है। ऐसे लोग जब श्रद्धा और नियम के साथ गुरुवार का व्रत करते हैं, तो धीरे-धीरे जीवन की उलझनें सुलझने लगती हैं। जिनकी आयु रेखा कमजोर होती है या जो बार-बार बीमारी, भय या दुर्घटनाओं से घिरे रहते हैं, उनके लिए भी गुरु की कृपा अत्यंत आवश्यक होती है, क्योंकि बृहस्पति को दीर्घायु और जीवन रक्षा का कारक माना गया है।

गुरु केवल भाग्य ही नहीं, सोच को भी नियंत्रित करते हैं। जब व्यक्ति की मानसिकता उथली हो जाती है, वह केवल तात्कालिक

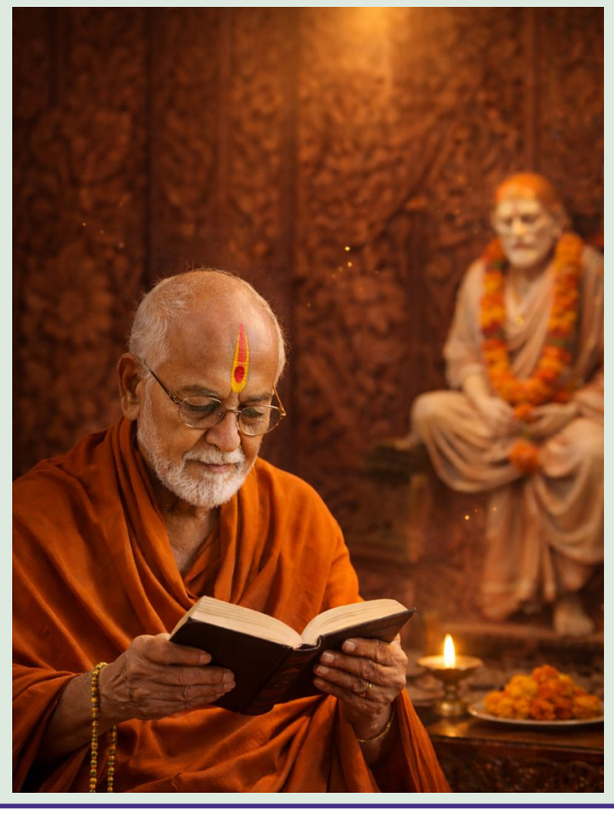

लाभ देखने लगता है और दूरगामी परिणामों की परवाह नहीं करता, तब समझना चाहिए कि गुरु कमजोर हो रहे हैं। गुरुवार का व्रत व्यक्ति के भीतर विवेक, धैर्य और सही-गलत की पहचान को पुनः जागृत करता है। यदि कुंडली में दशम भाव प्रभावित हो, पितृ दोष बन रहा हो या जीवन के हर मोड़ पर असफलता हाथ लग रही हो, तो गुरुवार का कठिन व्रत जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए कम से कम 11 गुरुवार का व्रत अवश्य करना चाहिए।

गुरुवार केवल भूखा रहने का दिन नहीं है। यह दिन आत्मशुद्धि और संकल्प का दिन माना गया है। इस दिन हल्दी, सफेद चंदन या गोरोचन का तिलक लगाने से गुरु तत्व मजबूत होता है। बुरी आदतें छोड़ने के लिए यह दिन अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि गुरुवार को लिया गया संकल्प लंबे समय तक निभता है। इस दिन किया गया प्रायश्चित पुराने पापों के प्रभाव को कम करता है और मन को हल्का करता है। उत्तर, पूर्व और ईशान दिशा में यात्रा करना शुभ माना जाता है। शिक्षा, धार्मिक कार्य, विवाह, प्रशासनिक निर्णय और संतान से जुड़े रचनात्मक कार्यों के लिए यह दिन विशेष फल देता है।

गुरुवार को घर में धूप-दीप, विशेषकर गुग्गुल की धूप देना, केवल धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक चिकित्सा मानी जाती है। इससे घर का वातावरण शुद्ध होता है, तनाव कम होता है और अनिद्रा जैसी समस्याओं में राहत मिलती है। मान्यता है कि इस दिन की गई धूप साधना से अदृश्य सहारा भी मिलता है, जिससे व्यक्ति को मानसिक मजबूती प्राप्त होती है।

यदि किसी का गुरु अत्यंत अशुभ हो, तो केवल व्रत ही नहीं, आचरण भी शुद्ध करना आवश्यक होता है। नित्य पीपल पर जल चढ़ाना, सत्य बोलना, पिता-दादा और गुरुजनों का सम्मान करना, पीली वस्तुओं का सेवन करना, पीतल के बर्तनों का प्रयोग, तिजोरी या ईशान कोण में हल्दी की गांठ रखना, सुबह-शाम कपूर जलाना और घर के वास्तु को गुरु तत्व के अनुसार संतुलित करना—ये सभी उपाय धीरे-धीरे जीवन की दिशा बदलने लगते हैं।

गुरुवार का व्रत व्यक्ति को केवल धार्मिक नहीं बनाता, बल्कि उसे भीतर से सुदृढ़ करता है। जब गुरु प्रसन्न होते हैं, तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं, निर्णय सही होने लगते हैं और जीवन में स्थिरता आने लगती है। शास्त्रों का यही संदेश है कि जब जीवन में सब कुछ होते हुए भी संतोष न मिले, तो समझ लेना चाहिए कि गुरु को मनाने का समय आ गया है।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH

राज्य की महानगर पालिकाओं और नगर पालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए 2800 करोड़ रुपए के चेक वितरण का गौरवशाली समारोह अहमदाबाद में आयोजित

▸▸ स्मार्ट सिटीज के अंतर्गत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से शुरू हुए 'सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन' कार्यक्रम में गुजरात देश के अग्रणी राज्यों में से एक : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल
▸▸ उप मुख्यमंत्री, शहरी विकास मंत्री और शहरी विकास राज्य मंत्री की उपस्थिति
▸▸ श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात से जो विकास पथ शुरू किया था, उस पर आज पूरा देश आगे बढ़ रहा है : उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी
▸▸ सुनिश्चित करें कि सभी विकास कार्य समय पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके पूर्ण हों : शहरी विकास मंत्री श्री कनुभाई देसाई

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल :-
▸▸ श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात ने देश के समक्ष यह उदाहरण पेश किया कि दूरदर्शी नेतृत्व और विकास के प्रति प्रतिबद्धता के साथ यदि धन की कमी न हो, तो शहरी विकास कितनी तेजी से किया जा सकता है
▸▸ जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के विरुद्ध राज्य के शहरों ने ग्रीन स्पेस, ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन मोबिलिटी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और स्वच्छ सर्वेक्षण में लीड ली है
▸▸ विकास के कार्यों में गुणवत्ता और स्वच्छता को वरीयता दें
▸▸ 2035 में जब हम गुजरात की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे, तब तक राज्य के शहरों को देश में उत्कृष्ट सुविधा युक्त शहर बनाने का अवसर है

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि स्मार्ट सिटीज के अंतर्गत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से शुरू हुए 'सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन' यानी नवाचार, एकीकरण और स्थिरता के लिए शहरी निवेश कार्यक्रम में गुजरात देश के अग्रणी राज्यों में से एक है।
इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए हमारे शहरों और महानगरों ने ग्रीन स्पेस, ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन मोबिलिटी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और स्वच्छता सर्वेक्षण में लीड ली है। इतना ही नहीं, सर्कुलर इकोनॉमी को गति देने के लिए चार 'आर' रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकल और रिकवर पर फोकस किया है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में 2005 में शहरी विकास वर्ष की शुरुआत की थी, यह वह दौर था जब देश में शहरीकरण को एक चुनौती माना जाता था। उन्होंने हमारी विरासत के अनुरूप शहरी विकास मॉडल विकसित करने के लिए बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की मजबूत नींव रखी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात ने श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में शहरी विकास वर्ष के जरिए इसका श्रेष्ठ उदाहरण पेश किया है कि, यदि दूरदर्शी नेतृत्व हो और विकास के प्रति प्रतिबद्धता के साथ धन की कोई कमी न हो, तो शहरी विकास कितनी तेजी से किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि शहरी विकास वर्ष 2005 की दो दशकों की सफलता के चलते मॉडर्न अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी आधुनिक शहरी परिवर्तन में बड़ा बदलाव आया है। इस परिवर्तन को और अधिक गति देने के लिए राज्य सरकार ने सर्वस्पर्शी, सर्वपोषक और सर्वसमावेशी नगरों के विकास के लक्ष्य को साकार करने के लिए 2025 को शहरी विकास वर्ष के रूप में मनाया है।
मुख्यमंत्री ने शहरी विकास वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में बुधवार को अहमदाबाद आयोजित कार्यक्रम में राज्य की महानगर पालिकाओं और नगर पालिकाओं को सर्वांगीण विकास कार्यों के लिए एक साथ, एक ही मंच से कुल 2800 करोड़ रुपए राशि के चेक वितरित किए।
मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी, शहरी विकास मंत्री श्री कनुभाई देसाई और राज्य मंत्री श्रीमती दर्शनाबेन वाघेला की उपस्थिति में राज्य की 8 महानगर पालिकाओं को कुल 2132 करोड़ रुपए तथा नवगठित 9 महानगर पालिकाओं को 40-40 करोड़ रुपए के हिसाब से कुल 360 करोड़ रुपए की राशि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कार्यों के लिए दी।
इसके अलावा, राज्य की 152 नगर पालिकाओं को कुल 308 करोड़ रुपए सहित कुल मिलाकर 2800 करोड़ रुपए विकास कार्यों के लिए प्रदान किए।
मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने ऐसा वित्तीय प्रबंधन किया है, जिसमें नगर पालिकाओं को विकास कार्यों के आयोजन में धन की कोई कमी रहे। अब नगर पालिकाओं को लोगों के विकास कार्यों के लिए अधिक से अधिक धन का उपयोग करने की क्षमता बढ़ानी होगी।
उन्होंने विकास कार्यों में गुणवत्ता और स्वच्छता को वरीयता देने का प्रेरक सुझाव देते हुए कहा कि स्वच्छता सभी का सहज स्वभाव बन गया है, ऐसे में नगर पालिकाओं और महानगर पालिकाओं को चाहिए कि वे इस दिशा में और अधिक पहल करने का दायित्व निभाएं।
श्री पटेल ने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण में उल्लेखनीय प्रगति करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर स्थान बनाने वाले राज्य के 6 शहरों का उल्लेख किया और उस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सभी शहरों को लीड लेने और प्रत्येक वार्ड में कचरे का 100 फीसदी पृथक्करण करने के साथ ही नगर पालिकाओं में बिजली बिल की बचत के लिए हरित एवं स्वच्छ सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लिए विकसित गुजरात के निर्माण का रोडमैप 'अर्निंग वेल, लिविंग वेल' के संकल्प के साथ तैयार किया गया है। 2047 के विकसित भारत से पहले, जब 2035 में गुजरात की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी, तब तक हमारे शहरों को देश में उत्कृष्ट सुविधा युक्त शहर बनाने का अवसर है।
उन्होंने महानगर पालिकाओं और नगर पालिकाओं से यह सुनिश्चित करने का भी अनुरोध किया कि नागरिक-केंद्रित सेवाओं और मोबाइल गवर्नेंस का दायरा बढ़ाते हुए सभी शहरों में टैक्स कलेक्शन और बिजली बिल सहित सभी बिलों के भुगतान के लिए यूपीआई के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए।
उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने इस मौके पर शहरी विकास के लिए एक ही स्थल से राज्य भर की महानगर पालिकाओं और नगर पालिकाओं को चेक वितरित करने के इस कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जनता की समस्याओं और मुश्किलों के समाधान के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं।
उन्होंने कहा कि राजस्व और शहरी विकास के क्षेत्र में समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए मुख्यमंत्री ने लगातार प्रयासरत रहते हुए जनकल्याण के अनेक कार्य पूर्ण कराए हैं। उन्हीं के कार्यकाल में स्वच्छता के क्षेत्र में राज्य के अनेक शहरों ने आगे बढ़कर देश में महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया है।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि तीन दशक पहले की सरकारों के दौर में लोगों को बुनियादी सुविधाओं के अभाव में निरंतर मुश्किलों के बीच जीना पड़ता था। लेकिन, श्री नरेन्द्र मोदी ने बतौर मुख्यमंत्री शासन की कमान संभालने के बाद गुजरात के शहर और जिले लगातार विकास के पथ पर तेज गति से आगे बढ़े हैं और आज पूरा देश विकास की इस तेज गति को देख रहा है। उन्होंने उच्च स्तरीय ढांचागत सुविधाओं के साथ नगरों के सतत विकास की चर्चा करते हुए कहा कि राज्य की 9 नगर पालिकाएं अब महानगर पालिका बन गई हैं। उन्होंने धोलेरा और गिफ्ट सिटी का उदाहरण देते हुए स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों से स्वच्छता और नागरिक सुविधाओं सहित अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए एक साथ आगे बढ़ने का अनुरोध किया।
शहरी विकास मंत्री श्री कनुभाई देसाई ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में गुजरात के विकास के लिए अनेक नए आयाम गढ़े और योजनाएं लागू कीं। उन्होंने ज्योतिग्राम योजना, शाला प्रवेशोत्सव और वाइब्रेंट गुजरात जैसी योजनाओं और अभियानों के अलावा आदिवासी विकास के लिए अलग से बजट आवंटन तथा 2009-10 में स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना शुरू की थी।
श्री देसाई ने कहा कि उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने शहरी विकास विभाग का बजट 22,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपए कर दिया है। शहरों में सड़क, सैनिटेशन, ड्रेनेज, स्टॉर्म वाटर सहित शहरी विकास की अन्य परियोजनाओं के लिए शहरी विकास विभाग लगातार काम कर रहा है। उन्होंने सभी महानगर पालिकाओं और नगर पालिकाओं के पदाधिकारियों से सभी विकास कार्यों को समय पर पूरा करने पर बल दिया।
शहरी विकास राज्य मंत्री श्रीमती दर्शनाबेन वाघेला ने स्वागत भाषण में कहा कि राज्य सरकार महानगर पालिकाओं और नगर पालिकाओं के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए सदैव कटिबद्ध है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की महानगर पालिकाओं और नगर पालिकाओं के सर्वांगीण विकास की लगातार चिंता की थी। उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने भी शहरी विकास विभाग के बजट में लगातार बढ़ोतरी कर लोगों की सुख-सुविधा बढ़ाने और अनेक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है।
इस अवसर पर राज्य के विभिन्न शहरी क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास की झलक दिखाने वाली लघु फिल्म भी दिखाई गई।
कार्यक्रम में विधानसभा के उप मुख्य सचेतक श्री जगदीशभाई मकवाणा, अहमदाबाद की महापौर श्रीमती प्रतिभा जैन, स्थानीय विधायक, शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव श्री एम. थेन्नारसन, कमिश्नर ऑफ म्युनिसिपैलिटीज श्रीमती रेम्या मोहन, म्युनिसिपल फाइनेंस बोर्ड की अपर आयुक्त श्रीमती वीमा पटेल सहित राज्य भर की महानगर पालिकाओं और नगर पालिकाओं के अधिकारी और पदाधिकारी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने दाऊदी बोहरा समाज के धर्मगुरु सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब से भेंट की

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने बुधवार को अहमदाबाद स्थित मजार-ए-कुत्बी में दाऊदी बोहरा समाज के सर्वोच्च धर्मगुरु सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब से शिष्टाचार भेंट की। यह भेंट दाऊदी बोहरा समाज के सर्वोच्च धर्मगुरु के अहमदाबाद के वार्षिक दौरे के दौरान हुई।
इस मुलाकात के दौरान सैयदना साहब ने जनकल्याण, सामाजिक समरसता और जिम्मेदार नागरिकता के महत्व पर चर्चा की।
उन्होंने अहमदाबाद के निरंतर हो रहे विकास और शहर की स्थिरता, व्यवस्था एवं नागरिक कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व की प्रशंसा की।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 32वें दाई सैयदना कुतबखान कुतुबुद्दीन साहब की पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी दरगाह पर पुष्पांजलि अर्पित की और शहर में इस समाज के इतिहास और विरासत की सराहना की।

तत्काल बुकिंग प्रणाली में बदलाव: अहमदाबाद मण्डल से चलने वाली और 3 ट्रेनों के लिए OTP प्रमाणीकरण 18 दिसंबर से लागू

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार तत्काल बुकिंग प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव लागू किया जा रहा है। अब तत्काल टिकट केवल सिस्टम द्वारा भेजे गए वन टाइम पासवर्ड (OTP) के सत्यापन के बाद ही जारी किए जाएंगे। यह ओटीपी उस मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा, जो यात्री द्वारा बुकिंग के समय दिया जाएगा। ओटीपी का सफल सत्यापन होने पर ही टिकट जारी किया जाएगा।
यह OTP-आधारित तत्काल प्रमाणीकरण प्रणाली 18 दिसम्बर, 2025 से निम्नलिखित ट्रेनों पर लागू हो जाएगी
1. ट्रेन संख्या 19223 साबरमती-जम्मू तवी एक्सप्रेस
2. ट्रेन संख्या 19316/19315 असारवा-इंदौर वीरभूमि एक्सप्रेस
3. ट्रेन संख्या 19489 अहमदाबाद– गोरखपुर एक्सप्रेस

निम्नलिखित ट्रेनों में 5 दिसंबर 2025 से OTP-आधारित तत्काल प्रमाणीकरण प्रणाली प्रारम्भ हो चुकी है।
1. ट्रेन संख्या 12957 साबरमती-नई दिल्ली स्वर्णजयंती राजधानी एक्सप्रेस
2. ट्रेन संख्या 12297 अहमदाबाद-पुणे दुरन्तो एक्सप्रेस
3. ट्रेन संख्या 12462 साबरमती-जोधपुर वंदे भारत एक्सप्रेस
4. ट्रेन संख्या 12268/12267 हापा–मुंबई सेंट्रल दुरंतो एक्सप्रेस
5. ट्रेन संख्या 12009/12010 मुंबई सेंट्रल-अहमदाबाद शताब्दी (01.12.2025 से लागू)

नई प्रणाली कंप्यूटरीकृत पीआरएस काउंटरों, अधिकृत एजेंटों, आईआरसीटीसी वेबसाइट तथा आईआरसीटीसी मोबाइल ऐप के माध्यम से की जाने वाली सभी तत्काल बुकिंग पर लागू होगी। यात्रियों से अनुरोध है कि वे बुकिंग के समय वैध मोबाइल नंबर अवश्य उपलब्ध कराएँ, ताकि OTP सत्यापन प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो सके। पश्चिम रेलवे द्वारा सभी यात्रियों से इस महत्वपूर्ण बदलाव पर ध्यान देने का आग्रह किया गया है।

कांदिवली और बोरीवली के बीच छठी लाइन कमीशनिंग के संबंध में नॉन इंटर्लोकिंग कार्य हेतु ब्लॉक के कारण कुछ ट्रेनें होंगी प्रभावित

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा कांदिवली और बोरीवली स्टेशनों के बीच छठी लाइन कमीशनिंग के संबंध में नॉन-इंटर्लोकिंग कार्य हेतु 20 दिसंबर 2025 से 30 दिन का ब्लॉक लिया जाएगा। जिसके कारण अहमदाबाद मण्डल से चलने/गुजरने वाली कुछ ट्रेनें प्रभावित रहेगी।जिसका विवरण निम्नानुसार है:
आंशिक निरस्त ट्रेनें:-
▸▸ ट्रेन संख्या 19418 अहमदाबाद-बोरीवली एक्सप्रेस 19 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025 तक वसई रोड पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी और वसई रोड एवं बोरीवली के बीच आंशिक रूप से निरस्त रहेगी।
▸▸ ट्रेन संख्या 19417 बोरीवली-अहमदाबाद एक्सप्रेस 21 दिसंबर से 30 दिसंबर 2025 तक वसई रोड से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी और वसई रोड एवं बोरीवली के बीच आंशिक रूप से निरस्त रहेगी।

रिशेड्यूल ट्रेनें
▸▸ ट्रेन संख्या 12902 अहमदाबाद-दादर गुजरात मेल अहमदाबाद से 27 दिसंबर 2025 को 01 घंटा, 10 एवं 15 जनवरी 2026 को 45 मिनट तथा 16 जनवरी 2026 को 30 मिनट रिशेड्यूल होगी।
▸▸ ट्रेन संख्या 22953 मुंबई सेंट्रल-अहमदाबाद गुजरात सुपरफास्ट एक्सप्रेस मुंबई सेंट्रल से 28 दिसंबर 2025 को 01 घंटा 35 मिनट, 11 जनवरी 2026 को 30 मिनट, 16 एवं 17 जनवरी 2026 को 50 मिनट रिशेड्यूल होगी।
▸▸ ट्रेन संख्या 20901 मुंबई सेंट्रल–गांधीनगर कैपिटल वंदे भारत एक्सप्रेस 28 दिसंबर 2025 को मुंबई सेंट्रल से 01.00 घंटा रिशेड्यूल होगी।
बोरीवली स्टेशन ठहराव नहीं करने वाली ट्रेनें
▸▸ ट्रेन संख्या 22928 अहमदाबाद-बांद्रा टर्मिनस लोकशक्ति एक्सप्रेस 27 दिसंबर 2025 को बोरीवली स्टेशन पर नहीं रुकेगी, इस दौरान यह ट्रेन वसई रोड और अंधेरी स्टेशनों पर ठहराव करेगी तथा 45-50 मिनट विलंब से पहुंचेगी।
▸▸ ट्रेन संख्या 22946 ओखा-मुंबई सेंट्रल सौराष्ट्र मेल 27 दिसंबर 2025 को बोरीवली स्टेशन पर नहीं रुकेगी, इस दौरान यह ट्रेन वसई रोड और अंधेरी स्टेशनों पर ठहराव करेगी तथा 45-50 मिनट विलंब से पहुंचेगी।
यात्रियों से अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्त बदलाव को ध्यान में रखकर यात्रा करें। ट्रेनों के ठहराव, समय और संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

सकारात्मक बातों के जरिये जीवन को खुशनुमा बनायें - श्रीमती मंजू लोढ़ा

आकृति आर्ट फाउंडेशन द्वारा 23 वीं अंतर्राष्ट्रीय समूह कला प्रदर्शनी का मुंबई में शुभारम्भ

(जीएनएस)। मुंबई, 17 दिसम्बर। सुप्रसिद्ध समाजसेवी, साहित्यकार और लोढ़ा फाउंडेशन की अध्यक्षा श्रीमती मंजू लोढ़ा ने कहा है कि हमारे आस-पास खुशियाँ देने वाली सकारात्मक ऊर्जा हमेशा बिखरी रहती है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते, बल्कि छोटी-छोटी बातों में उलझकर अपनी सोच को नकारात्मक बना लेते हैं। इसलिए अगर खुश रहना है, तो हमें सकारात्मक बातों के ज़रिये अपने जीवन को खुशनुमा बनाने की कला सीखनी चाहिये।
श्रीमती लोढ़ा मंगलवार, 16 दिसम्बर, 2025 की शाम देश की प्रमुख सांस्कृतिक, सामाजिक और कलात्मक संस्था *"आकृति आर्ट फाउंडेशन"* द्वारा आयोजित 23 वीं अंतर्राष्ट्रीय समूह कला प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अपने विचार व्यक्त कर रही थीं। उन्होंने इस प्रदर्शनी के आयोजन के लिए आकृति आर्ट फाउंडेशन के संस्थापक डायरेक्टर मनमोहन जायसवाल और सभी प्रतिभागी चित्रकारों को हार्दिक बधाई दी तथा उनकी निरंतर सफलता के लिए अनंत शुभकामनाएँ प्रकट कीं। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में बोलते हुए सुप्रसिद्ध गीतकार तथा मीडिया एवं जनसम्पर्क सलाहकार गजानन महतपुरकर ने कहा कि चित्रकला सचमुच ईश्वर की सच्ची भक्ति है, जिसमें चित्रकार अपने अंतर्मन के भावों की सुंदर अभिव्यक्ति करते हैं। उन्होंने मनमोहक कला प्रदर्शनी के लिए आयोजकों और प्रतिभागियों को हार्दिक बधाई दी। आकृति आर्ट फाउंडेशन के संस्थापक डायरेक्टर मनमोहन जायसवाल ने बताया कि उनकी संस्था पिछले 18 वर्षों से कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करती रही है। इसी क्रम में संस्था की 23 वीं अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित मेकर चैम्बर्स की आर्ट गैलेरी में 16 से 21 दिसम्बर तक लगाई गई है। उन्होंने बताया कि इस प्रदर्शनी में भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, दुबई और यूरोप से आये 35 प्रतिष्ठित कलाकार भाग ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे जल्दी ही अपनी टीम के साथ सभी कलाकारों के लिए डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म भी शुरू करने जा रहे हैं, जिससे आसानी से दुनिया के किसी भी कोने तक कलाकारों की कृतियाँ पहुँचाई जा सकती हैं। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के वरिष्ठ राजनेता अविनाश काम्बले, प्रमुख समाजसेवी एवं श्री नरेन्द्र मोदी की प्रतिमूर्ति विकास महंते, बजाज समूह की कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन हैड सुश्री सुरुचि महतपुरकर कोरे तथा ऑल स्टेट ग्रुप के चेयरमैन अजोयकांत रुइया सहित विभिन्न वक्ताओं ने प्रदर्शनी के बारे में अपने विचार व्यक्त किये। उल्लेखनीय है कि इस प्रदर्शनी में सुविख्यात चित्रकार एम एफ हुसैन, जामिनी रॉय, एस एच राजा, सोहन कुमार, पूर्वा तेनानी, प्रियेश, प्रधन्या पंडित, अनीता गोयल, संजना रामचंदानी, वैशाली शाह, प्रवीण पांडे, निशा गांधी, सलोनी गुप्ता, शोभना मेहता, सुनामदिनी जयंत, राजवी गांधी, निराली मोदी, राखी संघवी, रितिका सिंह, शेखर बर्वे, नंदा पाठक, सुमेध उन्नावने मयूर श्रीवंधनकर, नवाब जहान, तानिया फटनानी, ध्यानज्योति निंबालकर, शिवानी धुरिया, प्रीति शाह, आरती चोरड़िया, रूपाली मिस्त्री और श्रुति सोमन की पेंटिंग्स का प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में बहुत से कला प्रेमी, इंटीरियर डिजाइनर, आर्किटेक्ट तथा संगीत और साहित्य जगत के प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रारम्भ में श्री जायसवाल ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। विभिन्न अतिथिगणों द्वारा दीप प्रज्ज्वलन के साथ इस भव्य प्रदर्शनी की शुरुआत हुई, जो आगामी 21 दिसम्बर, 2025 तक रोज़ाना दोपहर 12 से रात्रि 8 बजे तक सभी कलाप्रेमी दर्शकों के निःशुल्क अवलोकनार्थ खुली रहेगी।

दिल्ली चुनाव में प्रचार की जंग में कांग्रेस आगे, खर्च में बीजेपी को छोड़ा पीछे, नतीजों में फिर भी खाली हाथ

(जीएनएस)। नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में नतीजों के साथ-साथ चुनावी खर्च को लेकर भी दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की रिपोर्ट के मुताबिक, कांग्रेस ने इस बार पार्टी प्रचार और सोशल मीडिया कैंपेन पर भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा पैसा खर्च किया, हालांकि उम्मीदवारों पर खर्च के मामले में वह पीछे रही। हैरानी की बात यह रही कि भारी खर्च के बावजूद कांग्रेस एक भी सीट जीतने में नाकाम रही, जबकि भाजपा ने 70 में से 48 सीटें जीतकर सत्ता पर कब्जा जमाया।
एडीआर की रिपोर्ट में चुनाव आयोग को दी गई पार्टियों की खर्च रिपोर्ट का विश्लेषण किया गया है। इसके अनुसार दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा ने कुल 57.65 करोड़ रुपये खर्च किए, जबकि कांग्रेस का कुल खर्च 46.19 करोड़ रुपये रहा। वहीं आम आदमी पार्टी का कुल चुनावी खर्च काफी कम, 14.5 करोड़ रुपये दर्ज किया गया। नतीजों की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने 22 सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल सका।
रिपोर्ट के मुताबिक, कांग्रेस ने प्रचार पर खास तौर पर सोशल मीडिया को अपना प्रमुख हथियार बनाया। सोशल मीडिया प्रचार पर कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 5.95 करोड़ रुपये खर्च किए, जबकि भाजपा ने इस मद में महज 5.26 लाख रुपये खर्च किए। आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पर लगभग 3 करोड़ रुपये खर्च किए। पार्टी प्रचार के कुल खर्च में भी कांग्रेस ने भाजपा को पीछे छोड़ दिया। कांग्रेस ने पार्टी प्रचार पर 40.13 करोड़ रुपये खर्च किए, जबकि भाजपा का यह खर्च 39.14 करोड़ रुपये रहा। आम आदमी पार्टी ने पार्टी प्रचार पर 12.12 करोड़ रुपये खर्च किए।
उम्मीदवारों पर खर्च के मामले में तस्वीर अलग नजर आई। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों पर अपेक्षाकृत कम राशि खर्च की, जबकि भाजपा ने इस मोर्चे पर ज्यादा निवेश किया। एडीआर के अनुसार, आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों पर 2.4 करोड़ रुपये खर्च किए, जिससे उसका कुल खर्च 14.5 करोड़ रुपये तक पहुंचा। भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवार खर्च को मिलाकर कुल 27 करोड़ रुपये का आंकड़ा सामने आया है।
चुनाव में फंड जुटाने के मामले में भाजपा सबसे आगे रही। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए भाजपा ने 88.7 करोड़ रुपये का फंड जुटाया, जबकि कांग्रेस को 64.3 करोड़ रुपये का चंदा मिला। आम आदमी पार्टी को इस दौरान 16.1 करोड़ रुपये का फंड प्राप्त हुआ। कुल मिलाकर सभी पार्टियों ने चुनाव के दौरान 170.68 करोड़ रुपये का फंड जमा किया। इनमें से ज्यादातर राशि पार्टियों के केंद्रीय मुख्यालय स्तर पर एकत्र की गई थी। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि अब तक नौ पार्टियों ने अपने खर्च का ब्यौरा दिया है, जिनका कुल खर्च 120.3 करोड़ रुपये रहा। इसमें 27 करोड़ रुपये उम्मीदवारों पर खर्च की गई राशि शामिल है। भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलावा बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी रही, जिसने 1 करोड़ रुपये से अधिक, यानी करीब 1.8 करोड़ रुपये खर्च किए।
दिलचस्प बात यह है कि 2020 और 2025 दोनों चुनाव लड़ने वाली छह पार्टियों के फंड में इस बार करीब 9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और यह आंकड़ा लगभग 170 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। वहीं खर्च के रुझान में बड़ा अंतर देखने को मिला। कांग्रेस के खर्च में पिछले चुनाव की तुलना में 222 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि भाजपा ने 2020 के मुकाबले लगभग 25 फीसदी कम खर्च किया। आम आदमी पार्टी के खर्च में भी करीब 6 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। एडीआर की यह रिपोर्ट एक बार फिर इस सवाल को सामने लाती है कि क्या ज्यादा पैसा खर्च करना चुनावी जीत की गारंटी है। दिल्ली चुनावों में कांग्रेस का उदाहरण दिखाता है कि आक्रामक प्रचार और सोशल मीडिया पर भारी निवेश के बावजूद जनसमर्थन हासिल करना आसान नहीं होता, जबकि भाजपा ने तुलनात्मक रूप से कम खर्च के साथ बड़ी चुनावी सफलता दर्ज की।

52,400 आगंतुकों के साथ खिजड़िया ने मजबूत की गुजरात की इको-टूरिज्म पहचान

▸▸ वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस में गुजरात की इकोलॉजिकल उत्कृष्टता के बेजोड़ उदाहरण के रूप में उभरेगा खिजड़िया पक्षी अभयारण्य
▸▸ रामसर साइट के दर्जे के साथ खिजड़िया अभयारण्य गुजरात के टिकाऊ विकास का जीवंत उदाहरण

(जीएनएस)। गांधीनगर : खिजड़िया पक्षी अभयारण्य ने वर्ष 2024-25 के दौरान 52,400 से अधिक सैलानियों को आकर्षित कर इको-टूरिज्म क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान को मजबूत किया है। राज्य में वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (वीजीआरसी) के लिए तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, तब यह अभयारण्य पारिस्थितिक (इकोलॉजिकल) उत्कृष्टता और टिकाऊ विकास के प्रति गुजरात की प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब बन रहा है। वीजीआरसी 2026 से पहले, जामनगर के निकट स्थित खिजड़िया रामसर स्थल गुजरात के महत्वपूर्ण पाकृतिक लैंडमार्क के रूप में उभरकर सामने आया है। कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र आज राज्य के अग्रणी पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित हो रहे हैं, जहां प्राकृतिक लैंडस्कैप, वन्यजीवन, तटीय सुंदरता, आध्यात्मिक स्थलों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अनोखा संगम देखने को मिलता है। सफेद रण से लेकर सौराष्ट्र के तीर्थ स्थलों, समुद्र तट और अभयारण्यों तक की यात्रा पर्यटकों को विविधतापूर्ण और यादगार अनुभव देती है।
600 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैला खिजड़िया पक्षी अभयारण्य मीठे और खारे पानी के दुर्लभ संगम के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। यह अनोखा पारिस्थितिक तंत्र पक्षियों के लिए एक विविधतापूर्ण

निवास उपलब्ध कराता है। गुजरात सरकार के वन एवं पर्यावरण विभाग के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023-24 के दौरान यहां 317 पक्षी प्रजातियां दर्ज की गई थी, जो 2024-25 में बढ़कर 332 हो गई है, जो इस अभयारण्य की लगातार विकसित होती जैव विविधता का प्रमाण है।
इस पारिस्थितिक समृद्धि को 2022 में वैश्विक मान्यता मिली, जब खिजड़िया को अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में रामसर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ। राज्य सरकार यहां पर्यटकों के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित कर रही है, जिसमें वॉच टावर, वन-कुटीर, पक्षी निरीक्षण प्लेटफॉर्म, इंटरप्रिटेशन सेंटर, सेल्फी पॉइंट और जानकारी देने वाले साइन बोर्ड शामिल हैं।
अभयारण्य की मुख्य ताकत इसके विविधतापूर्ण और सुरक्षित आवास स्थल में है, जहां मीठे पानी का बहाव समुद्री ज्वार के साथ मिलता है, और तटबंधों एवं खंदकों के नेटवर्क से यह और भी समृद्ध हो जाता है, जो वन्यजीवों के लिए आदर्श माइक्रोहैबिटेट यानी सूक्ष्म आवास बनाते हैं। ये सुविधाएं खिजड़िया को भारत के सबसे जीवंत पक्षी स्थलों में से एक बनाती हैं। साथ ही, यह आर्द्रभूमि (वेटलैंड) संरक्षण के प्रति गुजरात के वैज्ञानिक और योजनाबद्ध दृष्टिकोण को भी मजबूत बनाती है।
राजकोट में 10, 11 और 12 जनवरी, 2026 के दौरान आयोजित होने वाले वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस की पूर्व तैयारी के समय में, खिजड़िया पक्षी अभयारण्य गुजरात के एकीकृत विकास मॉडल का स्वाभाविक उदाहरण बनकर उभर रहा है, जहां पर्यावरणीय संरक्षण और आर्थिक विकास एक साथ आगे बढ़ते हैं। इस क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता कृषि, पर्यटन, जलवायु लचीलापन और टिकाऊ बुनियादी ढांचा जैसी राज्य की मुख्य पहलों की पूरक है, जिन पर वीजीआरसी के दौरान विशेष फोकस रहेगा।
खिजड़िया पक्षी अभयारण्य की यह सफलता गाथा गुजरात के 'सस्टेनेबिलिटी के साथ समृद्धि' के विजन के साथ गहराई से जुड़ी हुई है और आगामी क्षेत्रीय जुड़ाव मंच के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ के तौर पर उभर रही है।

द्वारकाधीश के दर्शन से पहले मातम, मोरबी में तेज रफ्तार ट्रक ने पांच पदयात्रियों को रौंदा, चार की दर्दनाक मौत

(जीएनएस)। मोरबी। गुजरात के मोरबी जिले में बुधवार सुबह एक बेहद हृदयविदारक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। द्वारका के लिए निकले श्रद्धालु पदयात्रियों का धार्मिक सफर उस समय मातम में बदल गया, जब मालिया तहसील के चाचावदरड़ा गांव के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से टक्कर मारते हुए पांच पदयात्रियों को कुचल दिया। इस भीषण हादसे में चार पदयात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया, जिससे घटना और भी दर्दनाक हो गई।

जानकारी के मुताबिक, वाव-थराद जिले की दियोदर और कांकरेज तहसील से कुल 11 श्रद्धालु 11 दिसंबर को पदयात्रा पर निकले थे। इन सभी का उद्देश्य द्वारकाधीश के दर्शन करना था। श्रद्धा और आस्था के साथ निकले ये यात्री मंगलवार रात को मोरबी जिले की मालिया तहसील के सरवाड गांव के पास स्थित सपेश्वर महादेव मंदिर में रुके थे। रातभर विश्राम के बाद बुधवार तड़के करीब पांच से छह बजे के बीच सभी ने दोबारा अपनी पदयात्रा शुरू की। सुबह की शांति और हल्की रोशनी के बीच जैसे ही पदयात्री चाचावदरड़ा गांव के पास पीपलिया हाइवे पर पेट्रोल पंप के नजदीक पहुंचे, पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। ट्रक की रफ्तार इतनी अधिक थी कि पांच पदयात्री संभल भी नहीं पाए। हादसे में वाव-थराद जिले की दियोदर तहसील के नवागाम निवासी दो सगे भाई भगवान चौधरी (65) और अमरा चौधरी (62), कांकरेज तहसील के अधगाम निवासी हार्दिक चौधरी (28) और दिलीप चौधरी (28) की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं नरसंग चौधरी (50) गंभीर रूप से घायल हो गए।

हादसे के बाद सड़क पर शव बिखरे देख वहां से गुजर रहे वाहन चालकों ने अपने वाहन रोक दिए, जिससे कुछ समय के लिए यातायात भी बाधित हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मालिया पुलिस और 108 एंबुलेंस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने सबसे पहले यातायात को सुचारु कराया और मृतकों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए मोरबी सिविल अस्पताल भिजवाया। घायल पदयात्री को भी गंभीर हालत में सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है।

हिट एंड रन की इस घटना के बाद पुलिस ने फरार ट्रक चालक की तलाश तेज कर दी है। आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं, ताकि ट्रक और चालक की पहचान की जा सके। पुलिस का कहना है कि दोषी चालक को जल्द गिरफ्तार कर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इस दर्दनाक हादसे की खबर मिलते ही टंकारा के विधायक दुर्लभजी देथरिया भी मोरबी सिविल अस्पताल पहुंचे। उन्होंने घायल पदयात्री से मुलाकात कर हालचाल जाना और मृतकों के साथियों को ढांढस बंधाया। विधायक ने मृतकों के शवों को उनके गृह क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं भी कराईं। द्वारकाधीश के दर्शन से ठीक पहले हुई इस त्रासदी ने न सिर्फ मालिया इलाके बल्कि वाव-थराद जिले में भी शोक की लहर फैला दी है। श्रद्धा के रास्ते पर निकले पदयात्रियों की ऐसी दर्दनाक मौत ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और तेज रफ्तार वाहनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पूरे क्षेत्र में माहौल गमगीन है और हर कोई दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना कर रहा है।

ई-मेल से फैली दहशत, दस स्कूल खाली कराए गए, अहमदाबाद में फर्जी बम धमकी से हड़कंप

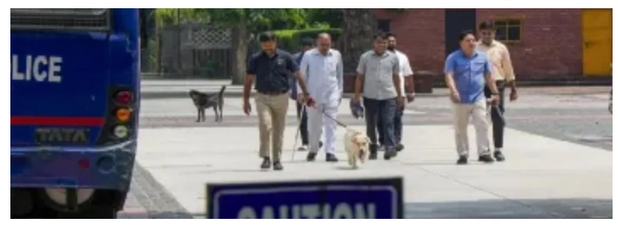

(जीएनएस)। अहमदाबाद। गुजरात के अहमदाबाद शहर में बुधवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब शहर के दस प्रमुख निजी स्कूलों को ई-मेल के जरिए बम विस्फोट की धमकी मिलने की सूचना सामने आई। अचानक आई इस धमकी ने अभिभावकों, छात्रों और स्कूल प्रशासन को दहशत में डाल दिया। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन हरकत में आ गया और एहतियातन सभी संबंधित स्कूलों को तुरंत खाली करा लिया गया। बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और दोपहर की पाली के लिए स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, धमकी भरे ई-मेल सुबह की पाली खत्म होने के बाद स्कूलों को प्राप्त हुए थे। मेल में दोपहर के समय स्कूल परिसरों में बम विस्फोट करने की बात कही गई थी। हालात की गंभीरता को देखते हुए किसी भी तरह का जोखिम न लेते हुए तुरंत सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किया गया। अभिभावकों को सूचित किया गया और छात्रों को सुरक्षित रूप से घर भेजा गया। स्कूल परिसरों के आसपास भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया, जिससे किसी तरह की अफवाह या भगदड़ की स्थिति न बने। जोन-1 के पुलिस उपायुक्त हर्षद पटेल ने बताया कि धमकी मिलने के तुरंत बाद अहमदाबाद पुलिस पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई। उनके नेतृत्व में कई पुलिस टीमें मौके पर पहुंचीं। बम निरोधक एवं निस्तारण दस्ता, श्वान दस्ता और विध्वंस-रोधी टीमें एक-एक स्कूल में पहुंचीं और व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया। कक्षाओं, गलियारों, सभागारों, पार्किंग एरिया और खुले मैदानों तक की बारीकी से जांच की गई। यह सर्च ऑपरेशन कई घंटों तक चला, ताकि किसी भी तरह की चूक न रह जाए।

घंटों की सघन जांच के बाद पुलिस ने राहत की खबर दी और स्पष्ट किया कि सभी धमकियां फर्जी थीं। किसी भी स्कूल परिसर से कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री बरामद नहीं हुई। इसके बाद प्रशासन ने स्थिति को पूरी तरह सुरक्षित घोषित किया, लेकिन इसके बावजूद एहतियातन कुछ समय तक पुलिस की मौजूदगी बनाए रखी गई।

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि जिन दस स्कूलों को धमकी भरे ई-मेल भेजे गए थे, उनकी सामग्री एक जैसी थी। हालांकि, जांच की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने ई-मेल के सटीक शब्दों या विवरण का खुलासा फिलहाल नहीं किया है। अब जांच का पूरा फोकस इस बात पर है कि ये ई-मेल किसने, कहां से और किस उद्देश्य से भेजे। अहमदाबाद पुलिस की साइबर क्राइम शाखा को इस मामले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साइबर विशेषज्ञ ई-मेल के आईपी एड्रेस, सर्वर लोकेशन और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं।

इस घटना के बाद अभिभावकों में भी चिंता देखी गई। कई माता-पिता स्कूलों के बाहर पहुंच गए और बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए। स्कूल प्रबंधन ने भरोसा दिलाया कि पुलिस और प्रशासन के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया गया और बच्चों की सुरक्षा में कोई कमी नहीं आने दी गई। पुलिस ने भी लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध सूचना की तुरंत पुलिस को जानकारी दें।

अहमदाबाद में फर्जी बम धमकी की यह घटना एक बार फिर यह सवाल खड़ा करती है कि शरारती तत्व किस तरह से डर और भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह की हरकतों की पुनरावृत्ति न हो और शहर में लोगों का सुरक्षा पर भरोसा बना रहे।

मेसी ने मारी किक, गुजरात के 'देसी मेसी' ने थामा इतिहास, एक फुटबॉल ने बदल दी महेश छांगा की जिंदगी

(जीएनएस)। अहमदाबाद/कच्छ। फुटबॉल के मैदान पर कभी-कभी ऐसे पल बनते हैं जो किसी खिलाड़ी या मैच से भी बड़े हो जाते हैं। अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर लियोनल मेसी के भारत दौरे के दौरान ऐसा ही एक लम्हा गुजरात के कच्छ जिले के एक छोटे से गांव धाणेटी के रहने वाले महेश छांगा की जिंदगी में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हुए इवेंट के दौरान मेसी ने जो फुटबॉल किक की, वही गेंद भीड़ को चीरती हुई सीधे महेश छांगा और उनके दोस्तों तक पहुंच गई। उस पल के बाद मानो 'मेसी बनाम मेसी' की कहानी जन्म ले गई, क्योंकि गांव में महेश को लोग पहले से ही प्यार से 'मेसी' कहकर बुलाते हैं।

महेश छांगा पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हैं, लेकिन दिल से फुटबॉल के जबरदस्त दीवाने। लियोनल मेसी के भारत आने की खबर मिलते ही उन्होंने अपने दोस्तों के साथ तय कर लिया था कि चाहे जो हो, मेसी को खेलते हुए देखना है। भुज तालुका के छोटे से गांव धाणेटी से निकलकर वे फ्लाइट से मुंबई पहुंचे। स्टेडियम में उन्हें नीचे की सीट नहीं मिली थी, लेकिन किस्मत शायद पहले से तय थी। जैसे ही मेसी ने आइकॉनिक किक मारी, गेंद सीधे उनके पास आ गिरी। भीड़ में मौजूद युवाओं ने उसे कैच किया और कुछ ही सेकंड में यह एहसास हो गया कि यह सिर्फ एक फुटबॉल नहीं, बल्कि जिंदगी का सबसे अनमोल पल है।

महेश बताते हैं कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉलर की किक की हुई गेंद उनके हाथों में आएगी। गेंद मिलते ही उन्होंने और उनके दोस्तों ने उसे चूम लिया। उस वक्त दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि शब्दों में बयान करना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि अगर नीचे की सीट मिल जाती, तो शायद यह ऐतिहासिक पल उनसे छूट जाता। किस्मत ने उन्हें वहीं बैठाया, जहां से इतिहास उनके हाथों में आ गिरा।

इस घटना के बाद महेश छांगा रातोंरात स्टार बन गए। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होते ही भुज और आसपास के इलाकों में लोग उनसे मिलने उमड़ पड़े। टीवी पर लाइव फुटेज देखने के बाद 200 से 300 लोग उनसे मिलने पहुंचे। हर कोई उस 'GOAT बॉल' के साथ फोटो खिंचवाना चाहता था। कुछ लोगों ने गेंद खरीदने के लिए मुंहमांगी कीमत तक ऑफर कर दी, तो कुछ ने सिर्फ सेल्फी के लिए हजारों रुपये देने की बात कही। लेकिन महेश ने साफ इनकार कर दिया। उनके लिए यह गेंद किसी कीमत से कहीं ज्यादा कीमती है। उन्होंने बिना किसी शुल्क के लोगों को फोटो क्लिक करने दी, क्योंकि उनके मुताबिक खुशी बांटने से बढ़ती है।

स्टेडियम से होटल तक का सफर भी कम रोमांचक नहीं था। महेश बताते हैं कि उन्होंने गेंद को 4-5 टी-शर्ट में लपेटकर बेहद संभालकर रखा, क्योंकि डर था कि कहीं यह अनमोल खजाना चोरी न हो जाए। उनके लिए यह सिर्फ फुटबॉल नहीं, बल्कि जिंदगी की सबसे बड़ी याद बन चुकी है। अब उनका इरादा है कि इस गेंद को धाणेटी के आहीर फुटबॉल क्लब में कांच के फ्रेम में सहेजकर रखा जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस पल को देख सकें और प्रेरित हो सकें।

लियोनल मेसी के भारत दौरे में कोलकाता से लेकर हैदराबाद और मुंबई तक जबरदस्त दीवानगी देखने को मिली। कहीं आयोजकों पर फैंस का गुस्सा फूटा, कहीं मुख्यमंत्री खुद मैदान पर उतरे, कहीं बॉलीवुड सितारों ने सेल्फी ली। लेकिन असली किस्मत तो गुजरात के इस छोटे से गांव के युवक की निकली, जिसने अपने हीरो की किक की हुई गेंद को थाम लिया। आज महेश छांगा और उनके साथ गए धाणेटी के नन्हे फुटबॉल प्रेमी देशभर में चर्चा का विषय हैं। यह कहानी सिर्फ एक गेंद की नहीं, बल्कि उस जुनून की है, जो किसी छोटे से गांव के युवा को दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉलर से जोड़ देता है।

भारत की रफ्तार बरकरार, मजबूत आर्थिक बुनियाद पर सात फीसदी से ज्यादा विकास की उम्मीद

(जीएनएस)। नई दिल्ली। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर एक बार फिर सकारात्मक संकेत मिले हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर लगभग सात फीसदी रहने की पूरी संभावना है। यह अनुमान आईएमएफ द्वारा अक्टूबर में जताए गए 6.6 फीसदी के पूर्व अनुमान से कहीं अधिक आशावादी है और यह दर्शाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक चुनौतियों के बावजूद मजबूती से आगे बढ़ रही है।

नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए गीता गोपीनाथ ने स्पष्ट किया कि आईएमएफ का पिछला अनुमान उस समय लगाया गया था, जब राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ओर से दूसरी तिमाही के आंकड़े सार्वजनिक नहीं हुए थे। जुलाई से सितंबर के बीच दूसरी तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 8.2 फीसदी दर्ज की गई, जो उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूत रही। उन्होंने कहा कि वास्तविक वृद्धि आठ फीसदी से ऊपर रहने का मतलब यह है कि पूरे वित्त वर्ष के लिए भी आर्थिक प्रदर्शन बेहतर रहने की संभावना बनती है। यही वजह है कि अब भारत की विकास दर को लेकर अनुमान और ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहे हैं।

गीता गोपीनाथ ने यह भी कहा कि यदि भारत को अपने दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों को हासिल करना है, तो केवल एक-दो वर्षों की तेज रफ्तार पर्याप्त नहीं होगी। उनके मुताबिक, अगर भारत अगले 20 वर्षों तक लगातार करीब आठ फीसदी की आर्थिक वृद्धि बनाए रखता है, तो वह वर्ष 2047 तक अपने विकास लक्ष्यों के बेहद करीब पहुंच सकता है। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि इतनी ऊंची और स्थिर वृद्धि दर हासिल करने के लिए निरंतर और प्रभावी आर्थिक सुधार बेहद जरूरी होंगे। निवेश, उत्पादकता, रोजगार सृजन और मानव संसाधन विकास जैसे क्षेत्रों में ठोस कदम उठाने होंगे, ताकि यह गति लंबे समय तक कायम रह सके। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर यह सकारात्मक दृष्टिकोण केवल आईएमएफ तक सीमित नहीं है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने भी देश की जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ाकर 7.3 फीसदी कर दिया है, जो पहले 6.8 फीसदी था। वहीं, वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने भी वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.9 फीसदी से बढ़ाकर 7.4 फीसदी कर दिया है। इन सभी अनुमानों से यह साफ संकेत मिलता है कि भारत की आर्थिक बुनियाद मजबूत बनी हुई है और देश वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में एक भरोसेमंद विकास इंजन के रूप में उभरता जा रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि घरेलू मांग में मजबूती, बुनियादी ढांचे में बढ़ता निवेश, सेवा और विनिर्माण क्षेत्रों का विस्तार और नीतिगत स्थिरता भारत की विकास गाथा को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रही है। अगर सुधारों की यह गति बनी रही, तो आने वाले वर्षों में भारत न केवल तेज विकास दर हासिल करेगा, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका और प्रभाव भी और मजबूत करेगा।

मिशन 2027 की तैयारी में 'आपरेशन झाड़ू', गुजरात के सियासी गढ़ में आम आदमी पार्टी की बड़ी सेंध

(जीएनएस)। अहमदाबाद। लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का अभेद्य किला माने जाने वाले गुजरात में आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए सियासी हलचल तेज कर दी है। 'गुजरात जोड़ो' अभियान के तहत आम आदमी पार्टी ने सूरत से ऐसा दावा किया है, जिसने बीजेपी और कांग्रेस—दोनों को झटका दिया है। पार्टी के अनुसार, सूरत में बीजेपी और कांग्रेस के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ईमानदार राजनीति के नाम पर आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। यह घटनाक्रम ऐसे समय पर सामने आया है, जब राज्य में 2026 के नगर निगम चुनाव नजदीक हैं और आम आदमी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारी में पूरी ताकत झोंक चुकी है। सूरत वही शहर है, जहां से आम आदमी पार्टी को गुजरात में पहली बड़ी राजनीतिक एंट्री मिली थी। वर्ष 2021 के नगर निगम चुनावों में आप ने सूरत में 27 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था और कांग्रेस को पीछे छोड़ते हुए सीधे विपक्ष की भूमिका हासिल कर ली थी। उसी जीत के बाद पार्टी ने 'मिशन गुजरात' की नींव रखी थी। अब एक बार फिर सूरत से उठी इस राजनीतिक हलचल को आम आदमी पार्टी अपनी रणनीतिक मजबूती का संकेत बता रही है।

पार्टी का दावा है कि शहर अध्यक्ष धर्मेश भंडेरी, लोकसभा अध्यक्ष रजनीकांत वघाणी, नवसारी लोकसभा प्रभारी पंकज तायडे और प्रवक्ता चित्रेश अनाजवाला की मौजूदगी में बीजेपी और कांग्रेस के कई नेताओं व कार्यकर्ताओं ने झाड़ू थाम ली। आम आदमी पार्टी के मुताबिक कांग्रेस युवा मोर्चा के राज्य कार्यकारिणी सदस्य और सूरत शहर के मंत्री भरत प्रजापति ने पार्टी जॉइन की है। उनके साथ उधना विधानसभा कांग्रेस अध्यक्ष अवधेश सिंह राजपूत भी आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। इन नेताओं के आने के बाद आप ने साफ संदेश दिया है कि वह आगामी नगर निगम चुनावों में मजबूत और ईमानदार उम्मीदवार मैदान में उतारेगी।

आम आदमी पार्टी का कहना है कि गुजरात में कांग्रेस पहले से ही कमजोर स्थिति में है और उसका संगठन जमीनी स्तर पर बिखरा हुआ है। ऐसे में आम आदमी पार्टी खुद को एक मजबूत विकल्प के तौर पर पेश करने में जुटी है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि बीजेपी के खिलाफ जनता में जो असंतोष है, उसका सीधा लाभ तभी मिलेगा, जब एक विश्वसनीय और सक्रिय विपक्ष मौजूद होगा। इसी रणनीति के तहत 'आपरेशन झाड़ू' को तेज किया गया है।

इस राजनीतिक हलचल को और अहम बनाता है सूरत का सियासी महत्व। सूरत राज्य के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी का गृह जनपद है और केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल भी इसी क्षेत्र से आते हैं। ऐसे में यहां बीजेपी से नेताओं और कार्यकर्ताओं का आम आदमी पार्टी की ओर रुख करना, पार्टी के लिए मनोवैज्ञानिक बढ़त माना जा रहा है। दिलचस्प बात यह भी है कि कुछ समय पहले सूरत में आम आदमी पार्टी के कई पार्षद बीजेपी में चले गए थे, लेकिन अब चुनावों से पहले तस्वीर बदलती नजर आ रही है और बीजेपी से आम आदमी पार्टी की ओर आने का सिलसिला शुरू हो गया है।

गुजरात में इस समय आम आदमी पार्टी के चार विधायक हैं। पार्टी ने हाल ही में अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उमेश मकवाणा को निष्कासित भी किया था, जिससे यह संदेश गया कि संगठन में अनुशासन और साफ छवि को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। गुजरात में पार्टी की कमान इसुदान गढ़वी के हाथों में है, जो 2022 के विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के चेहरा थे। अब वे संगठन को मजबूत करने और जमीनी विस्तार पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। गढ़वी ने सौराष्ट्र और आदिवासी बेल्ट में पार्टी को खासा चर्चा में ला दिया है।

हाल ही में आम आदमी पार्टी ने किसानों की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को ज्ञापन सौंपा था, जिससे यह साफ संकेत मिला कि पार्टी केवल चुनावी राजनीति तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि मुद्दों के जरिए जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। सूरत से शुरू हुई यह नई सियासी चाल आम आदमी पार्टी के लिए कितना बड़ा बदलाव लाएगी, यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि गुजरात की राजनीति में अब मुकाबला सिर्फ दो दलों तक सीमित नहीं रहा।

चांदी, चांदी-मिनी और चांदी-माइक्रो वायदा ऑल टाइम हाई स्तर पर पहुँचे: सोना वायदा में 173 रुपये की नरमी

क्रूड ऑयल वायदा 52 रुपये तेजः कमोडिटी वायदाओं में 45125.1 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 139566.38 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवरः सोना-चांदी के वायदाओं में 38578.72 करोड़ रुपये का हुआ कारोबारः बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 33071 पॉइंट के स्तर पर

(जीएनएस)। मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 184701.61 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 45125.1 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 139566.38 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का दिसंबर वायदा 33071 पॉइंट के स्तर पर ट्रेड हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 2479.13 करोड़ रुपये का हुआ। कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 38578.72 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना फरवरी वायदा 135079 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 135249 रुपये और नीचे में 133373 रुपये पर पहुंचकर, 134409 रुपये के पिछले बंद के सामने 173 रुपये या 0.13 फीसदी गिरकर 134236 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंचा। गोल्ड-गिनी दिसंबर वायदा 49 रुपये या 0.05 फीसदी की तेजी के संग 107578 रुपये प्रति 8 ग्राम हुआ। गोल्ड-पेटल दिसंबर वायदा 17 रुपये या 0.13 फीसदी की तेजी के संग 13466 रुपये प्रति 1 ग्राम हुआ। सोना-मिनी जनवरी वायदा सत्र के आरंभ में 132600 रुपये के भाव पर खूलकर, 133490 रुपये के दिन के उच्च और 132060 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 55 रुपये या 0.04 फीसदी की तेजी के संग 132682 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ। गोल्ड-टेन दिसंबर वायदा प्रति 10 ग्राम सत्र के आरंभ में 133419 रुपये के भाव पर खूलकर, 133784 रुपये के दिन के उच्च और 132358 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 132949 रुपये के पिछले बंद के सामने 95 रुपये या 0.07 फीसदी की तेजी के संग 133044 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ। चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा सत्र के आरंभ में 199201 रुपये के भाव पर खूलकर, 206111 रुपये के ऑल टाइम हाई और 199201 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 197755 रुपये के पिछले बंद के सामने 6920 रुपये या 3.5 फीसदी की बढ़त के साथ 204675 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था। इनके अलावा चांदी-मिनी फरवरी वायदा 6750 रुपये या 3.4 फीसदी की मजबूती के साथ 205150 रुपये प्रति किलो बोला गया। जबकि चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा 6837 रुपये या 3.45 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 205200 रुपये प्रति किलो पर आ गया। चांदी-मिनी फरवरी वायदा 206454 रुपये और चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा 206390 रुपये के ऑल टाइम हाई स्तर पर पहुँचा था। मेटल वर्ग में 3917.94 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा दिसंबर वायदा 5.1 रुपये या 0.46 फीसदी बढ़कर 1111 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि जस्ता दिसंबर वायदा 40 पैसे या 0.13 फीसदी बढ़कर 303.35 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। इसके सामने एल्यूमीनियम दिसंबर वायदा 1.1 रुपये या 0.39 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 2813 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा दिसंबर वायदा 85 पैसे या 0.47 फीसदी टूटकर 180.3 रुपये प्रति किलो हुआ।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 2622.03 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल दिसंबर वायदा 5095 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 5131 रुपये और नीचे में 5030 रुपये पर पहुंचकर, 52 रुपये या 1.03 फीसदी बढ़कर 5123 रुपये प्रति बैरल के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी दिसंबर वायदा 55 रुपये या 1.09 फीसदी की तेजी के संग 5124 रुपये प्रति बैरल के भाव पर पहुंचा। इनके अलावा नैचुरल गैस दिसंबर वायदा 359 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 366.2 रुपये और नीचे में 354.8 रुपये पर पहुंचकर, 356 रुपये के पिछले बंद के सामने 3.5 रुपये या 0.98 फीसदी बढ़कर 359.5 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि नैचुरल गैस-मिनी दिसंबर वायदा 3.6 रुपये या 1.01 फीसदी की तेजी के संग 359.5 रुपये प्रति एमएमबीटीयू हुआ। कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल दिसंबर वायदा सत्र के आरंभ में 945.5 रुपये के भाव पर खूलकर, 19.7 रुपये या 2.08 फीसदी की बढ़त के साथ 965.2 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था। कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 18213.50 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 20365.23 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 3058.01 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 352.64 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 21.83 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 485.45 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 992.80 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 1618.38 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 16905 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 77157 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 21981 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 346149 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 36990 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 17273 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 39352 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 112331 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 26254 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 40213 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स दिसंबर वायदा 33079 पॉइंट पर खूलकर, 33215 के उच्च और 33000 के नीचले स्तर को छूकर, 253 पॉइंट बढ़कर 33071 पॉइंट के स्तर पर ट्रेड हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल जनवरी 5100 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 31.6 रुपये की बढ़त के साथ 203 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस दिसंबर 360 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 1.55 रुपये की बढ़त के साथ 13.1 रुपये हुआ।

सोना दिसंबर 135000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 34.5 रुपये की गिरावट के साथ 1826 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी दिसंबर 205000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 3283.5 रुपये की बढ़त के साथ 5801.5 रुपये हुआ। तांबा दिसंबर 1120 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 2.36 रुपये की बढ़त के साथ 12.4 रुपये हुआ। जस्ता दिसंबर 310 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 15 पैसे के सुधार के साथ 2.01 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल जनवरी 5100 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 40.2 रुपये की गिरावट के साथ 167.5 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस दिसंबर 360 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 1.95 रुपये की गिरावट के साथ 13.8 रुपये हुआ।

सोना दिसंबर 128000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 11.5 रुपये की गिरावट के साथ 315 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी दिसंबर 200000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 2860 रुपये की गिरावट के साथ 3580 रुपये हुआ। तांबा दिसंबर 1100 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 1.89 रुपये की गिरावट के साथ 10.5 रुपये हुआ। जस्ता दिसंबर 300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 1.04 रुपये की बढ़त के साथ 3.35 रुपये हुआ।